



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 21, 2018/फाल्गुन 2, 1939

No. 70]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 2018/PHALGUNA 2, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2018

(अंतिम जांच परिणाम)

**विषय:** चीन जनवादी गणराज्य और टर्की के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "डिमेथिलेक्टामाइड" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

**सं. 14/41/2016-डीजीएडी:** समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे अधिनियम भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित उसकी सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. तथा मैसर्स बालाजी अमीन्स लि. (जिसे आगे यहां "याचिकाकर्ता" अथवा "आवेदक" कहा गया है) ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटन का आरोप लगाते हुए तथा परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति का आरोप लगाते हुए चीन जन. गण. तथा टर्की (जिन्हें आगे यहां "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "डिमेथिलेक्टामाइड" (जिसे आगे यहां "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने तथा पाटनरोधी जांच शुरू किए जाने के लिए अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे यहां प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है और संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

2. और जबकि प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 17.03.2017 की अधिसूचना संख्या 14/41/2016-डीजीएडी द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की जिसमें पाटनरोधी नियमावली के उप नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच की शुरुआत की गई ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगी।

**क. प्रक्रिया**

3. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:-

i. आवेदन की प्राथमिक जांच में कुछ कमियां सामने आई जिन्हें बाद में आवेदन ने ठीक कर लिया था। अतः आवेदन उचित रूप से दस्तावेजयुक्त माना गया था। प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में जांच शुरू करने का निर्णय लिया। प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित 17 मार्च, 2017 की अधिसूचना जारी की जिसमें संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की गई।

ii. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के उपनियम 5(5) के अनुसार जांच की कार्यवाही की शुरुआत करने से पहले पाटनरोधी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्राप्ति के संबंध में भारत में स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।

iii. जांच की शुरुआत करने के बाद प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार घरेलू उद्योग तथा ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को जांच की शुरुआत की एक प्रति भेजी और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरुआत की अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार देने का अनुरोध किया।

iv. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को तथा ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई। भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दें।

v. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावली भेजी।

- क. डुपोंट ट्रेडिंग (शंघाई) कं. लि., चीन जन गण
- ख. फार्मासीनो फार्मास्युटिकल्स (जियांग्सू), चीन जन गण
- ग. हेनन जुनहुआ डेवलेपमेंट कं. लि., चीन जन गण
- घ. सिनोकेम जियांग्सू कं. लि., चीन जन गण
- ङ. द केमोर्स केमिकल (शंघाई) कं. लि., चीन जन गण
- च. झेजियांग मेडिसिन्स एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स इम्पॉ. एंड एक्सपो. लि., चीन जन गण
- छ. अक-किम किमया ऐज, टर्की
- ज. डोरमेक्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स कं. लिमिटेड, टर्की
- झ. इनप्लास्ट प्लास्टिक, टर्की

vi. जांच की शुरुआत करने संबंधी अधिसूचना और सूचना के उत्तर में चीन जन. गण. के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर करते हुए उत्तर दिए हैं:

- क. हेनन जुनहुआ डेवलेपमेंट कं. लि., चीन जन. गण.
- ख. झेजियांग जियांगशन केमिकल कं. लि. चीन जन. गण.

vii. चीन जन. गण. के केवल हेनन जुनहुआ डेवलेपमेंट कं. लि. ने एमईटी का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए। तथापि, एमईटी का दावा बाद में वापस ले लिया गया है।

viii. निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर टर्की के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने नहीं दिया है। केवल भारत में टर्की के दूतावास द्वारा ही अनुरोध किए गए।

ix. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित उन ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशनों को जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रति भेजी, जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे और उन्हें सलाह दी कि वे नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।

- क. अमजे केम ट्रेड पी. लि.
- ख. भारत ज्योति इम्पेक्स
- ग. सी जे शाह एंड कं.

- घ. कार्मी इंटरनेशनल  
 ड. केमिकल सप्लायर्स इंडिया (पी) लि.  
 च. केमट्रेड ओवरसीज प्रा. लि.  
 छ. डेक्कन फाइन केमिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड  
 ज. धनुका लैबोरेट्रीज लि.  
 झ. हैवी केमिकल्स कूप  
 ञ. हिंदुस्तान स्पेशियलिटी केमिकल्स  
 ट. होसपीरा हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड  
 ठ. इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड  
 ड. जश फार्मा केम  
 ढ. के. उत्तमलाल एंड कंपनी  
 ण. केटुल केम प्रा. लि.
- i. किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने केमिकल सप्लायर्स इंडिया (पी) लि. को छोड़कर आयातक प्रभावली का उत्तर दायर नहीं किया और वह भी अपूर्ण है तथा निर्धारित तरीके से नहीं है। तथापि, उपर्युक्त आयातक द्वारा दायर उत्तर इस प्रकटन विवरण में किसी सीमा तक संगत पाया गया है।
  - ii. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
  - iii. क्षति रहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे निर्मित करने तथा उसकी बिक्री करने की लागत तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III पर आधारित है। इसे सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
  - iv. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें।
  - v. घरेलू उद्योग द्वारा तथा निर्यातकों द्वारा भी दी गई सूचना का सत्यापन आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक किया गया। केवल वह सत्यापित सूचना आवश्यक संशोधन के साथ, जहां भी लागू था, का उत्तर दिया गया। इसके अतिरिक्त, आवेदक एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक सूचना मांगी गई।
  - vi. जांच की अवधि के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क और उपलब्ध कराई गई सूचना, जिस सीमा तक वे साक्ष्य का समर्थन करती हैं और वर्तमान जांच में संगत मानी गई हैं, पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।
  - vii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 16.01.2018 को आयोजित मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी प्रदान किए। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे लिखित रूप में अपने अनुरोध दायर करें और प्रत्युत्तर भी दें तथा उन अनुरोधों पर विचार भी किया गया है।
  - viii. प्राधिकारी ने 1 अप्रैल, 2015 से 30 सितंबर मार्च, 2016 (18 माह) को जांच की अवधि के रूप में माना है ताकि सर्वाधिक हाल के आंकड़ों पर विश्लेषण किया जाए। इस प्रकार, जांच 1 अप्रैल, 2015 से 30 सितंबर, 2016 (जांच की अवधि) के लिए की गई थी। तथापि, क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल, 2012 – मार्च, 2013, अप्रैल, 2013 – मार्च, 2014, अप्रैल, 2014 – मार्च, 2015 और जांच की अवधि को शामिल किया गया है।

- ix. आवेदक द्वारा आवेदन में गौण स्रोतों (आईबीआईएस) के अनुसार आयात सूचना दी गई है और उस पर जांच की शुरुआत के स्तर पर विश्वास किया गया है। तथापि, प्राधिकारी ने पिछले वर्षों के लिए तथा इस जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि के लिए देश में संबद्ध सामानों के मूल्य और मात्रा के प्रयोजन के लिए डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लेन-देन बार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- x. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्ष ने न तो प्राधिकारी को उत्तर दिया है और न ही वर्तमान जाँच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना प्रस्तुत की है या जांच में काफी बाधा डाली है, उन्हें प्राधिकारी द्वारा असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उनके विचार रिकार्ड किए गए हैं।
- xi. इस अंतिम जाँच परिणाम में \*\*\* चिह्नकिसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।
- xii. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनायी गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 66.53 रुपये है।

#### ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. विचाराधीन उत्पाद डिमेथिलेक्तामाइड (एन, एन-डिमेथिलेक्तामाइड) है। डिमेथिलेक्तामाइड  $\text{CH}_3\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{CH}_3)_2$  वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका रासायनिक नाम "एन, एन-डिमेथिलेक्तामाइड" है। बाजार क्षेत्र में विचाराधीन उत्पाद को दर्शाने के लिए डीएमएसी जैसे संक्षिप्त रूप का भी प्रयोग किया जाता है। यह एक स्पष्ट रंगहीन से पानी में घुलनशील पीला द्रव और पीले अमीन जैसे अथवा अमोनिया स्वरूप का अन्य ऑर्गेनिक तत्व है।

5. संबद्ध सामानों का प्रयोग एथिलिक फाइबर के विनिर्माण में एक घोल, पॉलिस्टर फिल्मों के विनिर्माण में घोल, पेंट को हटाने, के लिए किया जाता है और उसके तेजी से हटाने की क्रिया के कारण पेंट की पट्टी में घोल के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा औषधि उद्योग में प्रतिक्रिया कारक के रूप में तथा घोल के रूप में प्रयुक्त होता है। यह उत्पाद खतरनाक रसायन है और सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित एचडीपीई ड्रमों में पैक किया जाता है।

6. विचाराधीन उत्पाद एक ऑर्गेनिक रसायन है जो सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 तथा साथ ही सीमा शुल्क उप शीर्ष संख्या 29241900 के तहत आता है जो कि विचाराधीन उत्पाद के लिए एक सम्पूर्ण उप शीर्ष नहीं है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि विचाराधीन उत्पाद को कि आयातों के समय सीमा शुल्क उप शीर्ष 29241900 के तहत प्राथमिक रूप से घोषित किया गया, तथापि, यह उप शीर्ष केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के आयात कई अन्य उप शीर्षों के तहत भी सूचित किए जाते हैं। याचिका के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद का आयात 29021100, 29051990, 29110090, 29152990, 29153990, 29211110, 29211190, 29212990, 29225090, 29241900, 29242190, 29242990, 29269000 और 20420090 जैसे अन्य उप शीर्षों के तहत भी किया गया है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और प्रस्तावित जांच के क्षेत्र पर एवं शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करने के किसी उपाय पर बाध्यकारी नहीं है।

7. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में समान वस्तु को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

*"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;*

8. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध सामानों और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। जैसा कि आवेदकों द्वारा अनुरोध किया गया है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसीलिए इन्हें इन नियमों के तहत "समान वस्तु" माना जाना चाहिए।

#### प्राधिकारी द्वारा जांच

9. विचाराधीन उत्पाद डिमेथिलेक्तामाइड (एन, एन-डिमेथिलेक्तामाइड) है। डिमेथिलेक्तामाइड  $\text{CH}_3\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{CH}_3)_2$  वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका रासायनिक नाम "एन, एन-डिमेथिलेक्तामाइड" है। बाजार क्षेत्र में विचाराधीन उत्पाद को दर्शाने के लिए डीएमएसी जैसे संक्षिप्त रूप का भी प्रयोग किया जाता है।

10. डिमेथिलेक्तामाइड स्पष्ट रंगहीन से पानी में घुलनशील पीला द्रव और पीले अमीन जैसे अथवा अमोनिया स्वरूप का अन्य ऑर्गेनिक तत्व है।

11. विचाराधीन उत्पाद एक ऑर्गेनिक रसायन है जो सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 तथा साथ ही सीमा शुल्क उप शीर्ष संख्या 29241900 के तहत आता है जो कि विचाराधीन उत्पाद के लिए एक सम्पूर्ण उप शीर्ष नहीं है। विचाराधीन उत्पाद विभिन्न अन्य उप शीर्षों के तहत भी आयातित किया जाता है जैसा कि आयात आंकड़ों से देखा गया है, इस प्रकार सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है तथा उत्पाद विवरण ही अकेला निपटानीय है।

12. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के दावों की जांच की है तथा नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों और संबद्ध देशों से निर्यातित सामानों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित संबद्ध सामान पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अभिप्राय से संबद्ध देशों से भारत में आयातित संबद्ध सामानों की समान वस्तु है।

13. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र एवं परिभाषा तथा समान वस्तु के पहलू की तुलना में किसी भी विरोधी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई तर्कसंगत अनुरोध नहीं किए गए हैं। तथापि, तुर्की दूतावास द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र सीमा शुल्क उप शीर्ष तक सीमित होना चाहिए न कि उससे आगे। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को सीमा शुल्क उप शीर्ष, जो कि यहां तक कि पूर्ण नहीं है, तक सीमित करना अनुकूल नहीं होगा और सीमा शुल्क प्रयोजनों के लिए विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पहचान करने के लिए मददकारी नहीं होगा। इसी के मद्देनजर यह पाया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक होंगे और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं होंगे।

#### ग. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार

14. वर्तमान पाटनरोधी जांच राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा बालाजी अमीन्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दायर किए गए आवेदन के आधार पर शुरू की गई थी।

15. आवेदकों ने दावा किया है कि वे केवल ही भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादक हैं। रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, आवेदक कंपनी के उत्पादन में घरेलू उत्पादन का "बड़ा अनुपात" है; वस्तुतः वह कुल घरेलू उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है।

16. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करता है:

*"2(ख) घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के नियतिकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।*

17. इस संबंध में संबद्ध तथ्यों की जांच करने के बाद और नियम के अनुसार यह नोट किया जाता है कि जिस आवेदन के आधार पर वर्तमान पाटनरोधी जांच शुरू की गई है, वह राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा बालाजी अमीन्स लिमिटेड द्वारा भारत में संबद्ध सामानों से संबंधित "घरेलू उद्योग" के रूप में संयुक्त रूप से दायर की गई है। राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा बालाजी अमीन्स लिमिटेड भारत में संबद्ध सामानों के एकमात्र उत्पादक पाए गए हैं। यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा इस तथ्य पर विवाद करते हुए कोई अनुरोध नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा यह भी दावा किया गया है कि उन्होंने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया और वे किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबंधित नहीं हैं।

18. चूंकि, आवेदक का उत्पादन भारत में संबद्ध सामानों के कुल उत्पादन में "बड़ा अनुपात" वस्तुतः 100 प्रतिशत बनता है, अतएव प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियम 5(3) के तहत आधार के मानदंड को पूरा करते हैं तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग हैं।

#### घ. गोपनीयता

19. विरोधी पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के पहलू के संबंध में कोई पर्याप्त अनुरोध नहीं किए गए हैं। तथापि, घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि उत्पादक/निर्यातक ने पूरक प्रश्नावली में दायर उत्तर में समस्त संगत सूचना गोपनीय रखी है और इससे घरेलू उद्योग कंपनी के संबंध में तथा चीन जन गण से उत्पादक/निर्यातक द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था

व्यवहार के दावे के आधार के संबंध में कोई वास्तविक मूल्यांकन नहीं कर पाया है। यह भी अनुरोध किया गया है कि इस प्रकार गोपनीय रखी गई सूचना के अभाव में उपलब्ध तथ्यों के साथ दावों की कोई संगति घरेलू उद्योग द्वारा नहीं की जा सकती।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

20. आवेदक द्वारा की गई गोपनीयता तथा प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई गोपनीयता के संबंध में अनुरोध की जांच की गई और उनका निम्नलिखित रूप में समाधान किया गया।

21. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

22. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

### ड. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

#### निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और हितबद्ध पक्षकारों के विचार

23. निर्यातकों, आयातकों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में इस दावे के अलावा, कोई महत्वपूर्ण अनुरोध नहीं किया गया है कि चीन जन गण को बाजार अर्थव्यवस्था देश माना जाना चाहिए और यह कि चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य उनकी लागू लागत और कीमत के आधार पर होना चाहिए। तथापि, एक भागीदार उत्पादक/निर्यातक द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) के दावे को वापस भी ले लिया गया है।

#### घरेलू उद्योग के विचार

24. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन और एमईटी दावों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. याचिका में दिए गए अनुसार पाटन मार्जिन नियमावली में दिए गए अनुसार न्यूनतम से अधिक हैं और दोनों संबंध देशों यथा चीन जन गण और टर्की से निर्यात के मामले में काफी भी हैं।
- ख. केवल दो निर्यातकों ने चीन जन. गण. से वर्तमान जांच में उत्तर दिए। तथापि, टर्की से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने कोई उत्तर दायर नहीं किए। टर्की से किसी उत्पादक/निर्यातक से किसी भी निर्यातक प्रश्नावली (ईक्यू) के उत्तर के अभाव में टर्की के मामले में पाटन मार्जिन/क्षति मार्जिन, क्षति मार्जिन के प्रयोजन के लिए भारत में पहुँच कीमत निर्धारित करने के लिए संगत ब्यौरों सहित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में याचिका में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।
- ग. चीन जन. गण. के मामले में दो उत्पादकों/निर्यातकों, जिन्होंने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं, में से एक ने एमईटी का दावा किया है। अनुरोध है कि ऐसे पक्षकारों को अलग से कोई भी मार्जिन दावे के सत्यापन के लिए भारत को उनके निर्यात के संबंध में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर की कठोर जांच के अध्यक्षीन रखा जाए।

- घ. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए चीन जन गण को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए तथा चीन उत्पादक एवं निर्यातकों के मामले में सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ङ. हेनन जुनहुआ डेवलेपमेंट कं. लि. को निम्नलिखित कारणों से उसके उत्तर के आधार पर कोई एमईटी नहीं दिया गया है कि यह कंपनी हेनन जुनहुआ डेवलेपमेंट कं. लि. चीन जन गण में एक बड़ी समूह कंपनी का भाग है और एमईटी प्रश्नावली का उत्तर उस समूह ने दायर नहीं किया, (ख) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि वे हेनन जुनहुआ डेवलेपमेंट कं. लि. अंततः चीन नेशनल केमिकल कारपोरेशन के स्वामित्व वाली कंपनी है जो कि सरकारी स्वामित्व का उद्यम है। हेनन जुनहुआ डेवलेपमेंट कं. लि. का अंतिम स्वामित्व सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम में होने के कारण एमईटी के उसके दावे सिद्ध करने के लिए उसकी शुरुआत से विभिन्न तथ्य सिद्ध करने की आवश्यकता है, (ग) यद्यपि अंतिम स्वामी चीन नेशनल केमिकल कारपोरेशन देखा जाता है, अतः सूचना यह दर्शाती है कि हेनन जुनहुआ डेवलेपमेंट कं. लि. हाओहुआ जुनहुआ और हाओहुआ जुनहुआ ग्रुप कं. लि. की एक सहायक कंपनी है जो कि चीन नेशनल केमिकल कारपोरेशन के तहत आती है। यहां तक कि हाओहुआ जुनहुआ ग्रुप कं. लि. एमईटी का उत्तर दायर कर प्राधिकारी के समक्ष नहीं आई है।
- च. सरकारी स्वामित्व हेनन जुनहुआ डेवलेपमेंट कं. लि. के संबंध में कई प्रश्न उठाता है। कंपनी तथ्यों पर आधारित यह सिद्ध करने की आवश्यकता है कि निवेश के व्यौरों सहित संयंत्र की स्थापना कैसे की गई थी, निवेश किसने किया, निधियों का स्रोत क्या था, कंपनी ने कहां पर किससे भूमि ली तथा भूमि के लिए भुगतान कैसे किए गए, कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों के व्यौरे क्या हैं, कंपनी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ऐतिहासिक रूप से कैसे पूरी की गई, कच्ची सामग्री और उपयोगी वस्तुओं आदि के स्रोत क्या थे तथा यह सिद्ध करने के लिए भी धारक कंपनियों के रिकार्ड के साथ ऐसे व्यौरे रखे जाने की आवश्यकता है कि कंपनी की लागत बाजार सिद्धांतों को दर्शाती है और सरकारी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं है।
- छ. उपलब्ध तथ्यों के आधार पर हेनन जुनहुआ डेवलेपमेंट कं. लि. बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत प्रचालन नहीं करती और इसीलिए कंपनी की उत्पादन लागत एमई सिद्धांतों के आधार पर नहीं मानी जा सकती। घरेलू उद्योग ऐसे उत्पादक के साथ प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकता जिनकी लागत सरकारी हस्तक्षेप से प्रभावित हो और कुल मिलाकर हेनन जुनहुआ डेवलेपमेंट कं. लि. के एमईटी दावों का रद्द किया जाना चाहिए।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

25. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में यह अनुरोध है कि डब्ल्यूटीओ के साथ चीन द्वारा हस्ताक्षरित अभिगमन नयाचार के पैरा 15(क)(i) के तहत प्रतिबद्धताओं की अपेक्षा है कि जांच के अधीन उत्पादकों को स्पष्ट रूप से यह दर्शाना चाहिए कि विनिर्माण, उत्पादन और उत्पाद की बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग ने बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। यह सिद्ध किए जाने की स्थिति में आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य तुलनात्मक रूप से कीमत निर्धारित में जांच के अधीन उद्योग के लिए चीनी कीमत अथवा लागत का प्रयोग कर सकेगा। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 तथा भारत की पाटनरोधी नियमावली में यह अपेक्षा है कि उत्पादक/निर्यातक के वित्तीय रिकार्ड पर्याप्त रूप से उत्पादन लागत दर्शाएं। अतः निम्नलिखित के संबंध में उसकी सूचना और समर्थक साक्ष्य दिए जाने की आवश्यकता है:

- क. कच्ची सामग्री, प्रौद्योगिकी की लागत तथा श्रम, उत्पादन, बिक्री और निवेश सहित कीमत, लागत, इनपुट के संबंध में निर्णय आपूर्ति एवं मांग दर्शाने वाले बाजार संकेत के उत्तर में तथा बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के किये जाते हैं और यह भी देखा जाता है कि क्या प्रमुख इनपुट की लागत पर्याप्त रूप से बाजार मूल्य दर्शाती है।
- ख. उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति किसी ह्रास से प्रभावित नहीं होती।
- ग. उत्पादक/निर्यातक दिवालियापन तथा संपत्ति कानून के अध्याधीन हैं जो कि फर्म के प्रचालन के लिए कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं।
- घ. विनिमय दर परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं।

26. यह नोट किया जाता है कि केवल हेनन जुनहुआ डेवलेपमेंट कं. लि., जो चीन जन गण से संबद्ध सामानों का उत्पादक एवं निर्यातक है, ने वर्तमान जांच में एमईटी का दावा किया है। तथापि, हेनन जुनहुआ डेवलेपमेंट कं. लि. ने बाद में जांच की अवधि के दौरान अपने बाजार अर्थव्यवस्था के दावे को वापस ले लिया है। तदनुसार, चीन के संबंध में सामान्य मूल्य निर्मित किया गया है।

27. हेनन जुनहुआ डेवलेपमेंट कं. लि. द्वारा किए गए एमईटी दावों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्कों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि यह अनिवार्य नहीं है कि एमईटी के दावे की वापसी के मद्देनजर इन तर्कों को विस्तार से समाधान किया जाए।

**क. सामान्य मूल्य का निर्धारण**

**i. चीन जन गण**

28. तदनुसार, किसी भी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध सामानों के लिए कोई विश्वसनीय कीमत एवं लागत के ब्यौरे न होने की वजह से प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग एवं उपयुक्त लाभ के सबसे प्रभावी घटक की परिवर्तन लागत तथा कच्ची सामग्री और उपयोगी वस्तुओं के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री एवं उपभोग मानदंडों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर विचार करते हुए चीन जन गण के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया है। चीन जन गण से सभी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

**ii. टर्की**

29. यह नोट किया जाता है कि टर्की से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए अथवा उत्तर नहीं दिया है। इसी के मद्देनजर, टर्की के सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग एवं उपयुक्त लाभ के सबसे प्रभावी घटक की अधिकतम लागत एवं खपत मानदंडों पर विचार करते हुए निर्मित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

**ख. निर्यात कीमत का निर्धारण**

**i. चीन जन गण**

**(क) हेनन जुनहुआ डेवलेपमेंट कं. लि., चीन जन गण**

30. प्राधिकारी हेनन जुनहुआ डेवलेपमेंट कं. लि. द्वारा दायर निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर से नोट करते हैं कि कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान भारत को सीधे ही संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। निर्यातक ने अपने परिशिष्ट-2 में भारत को अपना निर्यात सूचित किया है तथा अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, बीमा एवं बैंक प्रभार, ऋण लागत, वापस न किए जाने वाला वैट, पत्तन सार संभाल प्रभारों के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और वह उन्हें दिया गया है। तदनुसार, निर्धारित निवल निर्यात कीमत इस निर्यातक के लिए निर्धारित की गई है और वह निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

**(ख) झेजियांग जियांगशन केमिकल कं. लि., चीन जन गण**

31. प्राधिकारी झेजियांग जियांगशन केमिकल कं. लि. द्वारा दायर निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर से नोट करते हैं कि कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान भारत को सीधे ही संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। निर्यातक ने अपने परिशिष्ट-2 में भारत को अपना निर्यात सूचित किया है तथा अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, बीमा एवं बैंक प्रभार, ऋण लागत, वापस न किए जाने वाला वैट, पत्तन सार संभाल प्रभारों के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और वह उन्हें दिया गया है। तदनुसार, निर्धारित निवल निर्यात कीमत इस निर्यातक के लिए निर्धारित की गई है और वह निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

**(ग) चीन जन गण से अन्य सभी असहयोगी उत्पादक/निर्यातक**

32 प्राधिकारी ने रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार, अन्य असहयोगी निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है। इस प्रकार, निर्धारित निवल निर्यात कीमत निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

**(ii) टर्की**

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि टर्की से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। इस असहयोग के मद्देनजर प्राधिकारी ने याचिका द्वारा दावा किए गए देय समायोजनों के साथ डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के आधार पर टर्की के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है तथा इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

**ग. पाटन मार्जिन का निर्धारण**

34. उपर्युक्त निर्धारित सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के आधार पर संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित है।



क्रम सं.	देश	उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य - अमेरिकी डॉलर/मी. टन	निबल निर्यात कीमत - अमेरिकी डॉलर/मी. टन	पाटन मार्जिन - अमेरिकी डॉलर/मी. टन	पाटन मार्जिन - %	पाटन मार्जिन रेंज - %
1	चीन जन गण	हेनन जुनहुआ डेवलेपमेंट कं. लि.	हेनन जुनहुआ डेवलेपमेंट कं. लि.	***	***	***	***	20-30
2	चीन जन गण	झेजियांग जियांगशन केमिकल कं. लि.	झेजियांग जियांगशन केमिकल कं. लि.	***	***	***	***	10-20
3	चीन जन गण	कोई अन्य	कोई अन्य	***	***	***	***	25-35
4	टर्की	कोई अन्य	कोई अन्य	***	***	***	***	25-35

### च. क्षति निर्धारण

#### i. क्षति की जांच

#### निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

35. निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए क्षति संबंधी अनुरोध संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

- क. याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए आवश्यक स्थिति सिद्ध करने का कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं दिया है। यह सलाह दी जाती है कि वर्तमान जांच की शुरुआत रद्द की जाए।
- ख. डीएमएसी के आयातों पर पाटनरोधी उपाय लगाने तथा जांच के लिए याचिकाकर्ता का आवेदन में स्पष्ट रूप से कानूनी एवं वास्तविक आधार की कमी है।
- ग. रिकार्ड में उपलब्ध तथ्य यह बताते हैं कि याचिकाकर्ता ने संबद्ध उत्पाद का बड़ा हुआ आयात अत्यधिक बढ़कर बताया है और घरेलू उद्योग को क्षति जान-बूझकर तैयार की है। परिणामस्वरूप यदि जांचकर्ता प्राधिकारी जांच जारी रखते हैं तो यह निर्धारित किया जाएगा कि उस संबद्ध उत्पाद में कोई वृद्धि नहीं हुई है जिससे याचिकाकर्ता को क्षति हुई है।
- घ. निर्यातक का यह मत है कि याचिकाकर्ता के लिए गंभीर क्षति का दावा करने हेतु कोई कानूनी एवं वास्तविक आधार नहीं है। अतः भारतीय प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे तदनुसार दावे को रद्द करें। याचिकाकर्ता के दावे प्रकाशित सूचना के विपरीत हैं तथा याचिकाकर्ता को बनावटी क्षति दर्शाते हैं।
- ङ. घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री लगभग समान रही और घरेलू उद्योग ने उस समय कमजोर तरीके से निष्पादन किया जब मांग बहुत अधिक थी।
- च. आयात की पहुँच कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के बीच कोई सह संबंध नहीं है क्योंकि जांच की अवधि में पहुँच कीमत में गिरावट आई है जबकि बिक्री कीमत बढ़ी है।
- छ. याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री में अत्यधिक ह्रास नहीं हुआ है।
- ज. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जांच की अवधि के दौरान बढ़ा है।
- झ. क्षति का एक प्रमुख कारण कर्मचारियों की संख्या और मजदूरी में वृद्धि है।
- ञ. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग बढ़ा है।
- ट. कीमत कटौती पूरी क्षति अवधि में नकारात्मक रही है। यह कोई कीमत प्रभाव नहीं दर्शाता।

- ठ. चूंकि, घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता बढ़ाई है, अतः घरेलू उद्योग के सामने पूंजीगत निवेश बढ़ाने के लिए अपनी क्षमता से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है।
- ड. एक उत्पादक अर्थात् बालाजी अमीन्स लिमिटेड अच्छा चल रहा है और उपर्युक्त कारणों से विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद के बीच लागत आबंटन की जांच की जानी चाहिए।
- ढ. एनआईपी के प्रयोजन के लिए 22 प्रतिशत आरओआई वर्तमान मामले में औचित्यपूर्ण नहीं है। इस संबंध में माननीय सेसटेट के निर्णय हैं जो दर्शाते हैं कि आयातक को ही एनआईपी के प्रयोजन के लिए वह प्रतिशतता लागू करनी है।
- ण. संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद का कोई पाटन नहीं है तथा आयातित उत्पादों से भारतीय घरेलू उद्योग को कोई क्षति अथवा क्षति का खतरा नहीं हुआ है। इस मामले में पाटनरोधी उपाय लागू करना भारतीय घरेलू उद्योग और उसके निचले उद्योगों के दीर्घावधि एवं समग्र हितों के लिए असंगत होगा।
- त. निर्यातकों का विश्वास है कि पाटनरोधी जांच का प्रयोजन उचित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था का संरक्षण करना है। व्यापार संरक्षण के साधन के रूप में पाटनरोधी उपाय के अनुचित कार्यान्वयन से एक अनुचित प्रतिस्पर्द्धा का वातावरण बनेगा और लम्बे समय में उनके संबंधित उद्योगों के मौलिक हितों को क्षति पहुँचेगी।
- थ. विचाराधीन उत्पाद से संबंधित टर्की के समर्पित कोड के अनुसार भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात कम हुआ है। ऐसे परिदृश्य में टर्की से आयात भारत में विचाराधीन उत्पादों के आयातों में वृद्धि का कारण नहीं है। भारत हमेशा टर्की के विरुद्ध व्यापार अधिशेष का फायदा उठाता रहा है जो वार्षिक रूप से 5-6 बिलियन की दर पर है।
- द. वर्तमान मामले में कोई संचयी मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए और चीन एवं टर्की से आयातों के प्रभाव की अलग से जांच की जानी चाहिए।
- ध. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने विभिन्न मानदंडों के संबंध में सकारात्मक प्रवृत्तियाँ दर्शाई हैं। यह प्रवृत्ति बाजार हिस्सा, बिक्री, उत्पादन, क्षमता, उत्पादकता, लाभ, निवेश आदि की दृष्टि से सकारात्मक रही।
- न. टर्की से आयातों से क्षति न होने के मद्देनजर भारतीय प्राधिकारी को पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.2 और भारतीय पाटनरोधी कानूनों के अनुरूप कार्य करना चाहिए जिससे वर्तमान मामला रद्द होगा।
- प. निर्यातकों ने जांच की शुरुआत के समय (17 जनवरी, 2017), जांच की शुरुआत के बाद (28 अप्रैल, 2017) और लिखित अनुरोध (23 जनवरी, 2018) के समय विभिन्न अवसरों पर घरेलू उद्योग द्वारा दायर आंकड़ों की असंगतता का मुद्दा उठाया है।
36. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति से संबंधित अनुरोध संक्षेप में निम्नलिखित हैं:
- क. वर्तमान जांच के लिए संगत क्षति संबंधी आंकड़े यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।
- ख. क्षति संबंधी विवरण से यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात क्षति की अवधि में काफी बढ़े हैं। आयात की मात्रा, जो आधार वर्ष में लगभग 2319 एमटी थी, वह बढ़कर जांच की अवधि में 3501 एमटी के स्तर तक हो गई। यद्यपि आधार वर्ष में टर्की से आयात जांच की अवधि तक कम हुए। तथापि, भारत में कुल आयातों में प्रतिशतता की दृष्टि से आयात लगभग 18 प्रतिशत रहे जो कि 3 प्रतिशत के सांविधिक आरंभिक स्तर से कहीं अधिक है और पाटन कीमतें थीं।
- ग. यद्यपि संबद्ध देशों से आयात पूरे तौर पर तथा उत्पादन एवं खपत के संबंध में भी काफी बढ़े। तथापि, आयात कीमत, जो 2012-13 में लगभग 76.14 प्रति किलोग्राम (सीआईएफ) थी, वह घटकर जांच की अवधि में 71.17 प्रति किलोग्राम (सीआईएफ) हो गई। वस्तुतः दोनों देशों से आयात कीमत में कमी आई है और टर्की से ऐसे आयात में पाटन मार्जिन की स्थिति 15-30 प्रतिशत की दर पर है तथा चीन जन गण से वह 20-35 प्रतिशत की दर पर है।
- घ. कंपनी में क्षमता पूरी क्षति की अवधि के दौरान 7500 मीट्रिक टन रही है और उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग तथा बिक्री क्षति की अवधि में आंशिक रूप से वृद्धि है, परंतु पाटित सामग्री की मौजूदगी के कारण बराबर स्तरों से नीचे रही है। क्षमता उपयोग जांच की अवधि में लगभग केवल 53.66 प्रतिशत था जो आधार वर्ष में लगभग 45 प्रतिशत था। क्षमता उपयोग का यह निम्न स्तर क्षमता उपयोग के किसी उपयुक्त स्तर के रूप में नहीं देखा जा सकता तथा यह निम्न क्षमता उपयोग भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के अत्यधिक आने के परिणामस्वरूप है। इस प्रकार, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री के कम स्तरों के संदर्भ में वास्तविक क्षति बहुत ही स्पष्ट है।

- ड. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा, जो आधार वर्ष में 44 प्रतिशत था, वह 48 प्रतिशत तक बढ़ पाया जबकि पाटित आयातों का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में 31 प्रतिशत से बढ़कर जांच की अवधि में 44 प्रतिशत हो गया जो यह दर्शाता है कि पाटित आयात अनुकूल एवं महत्वपूर्ण तरीके से बाजार हिस्से को ले रहे हैं। इस प्रकार, बाजार हिस्से के कारण क्षति दिखाई दे रही है। पाटित आयातों के अभाव में घरेलू उद्योग ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग के अनुरूप उत्पादन किया होता और काफी बिक्री की होती।
- च. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत 100 प्रतिशत के आधार बिंदु से बढ़कर जांच की अवधि में 129 के बिंदु तक बढ़ गई जबकि बिक्री कीमत केवल 103 बिंदु तक बढ़ पाई जो यह दर्शाता है कि बिक्री कीमत में वृद्धि उत्पादन की लागत में वृद्धि से काफी कम थी। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण ग्राहकों को अपनी पूरी लागत पर भी आगे देने की स्थिति में नहीं था। घरेलू उद्योग को वस्तुतः क्षति की अवधि के दौरान नकद हानियां हो रही थीं। इस प्रकार, कीमत न्यूनीकरण और ह्रास स्पष्ट हैं।
- छ. संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमतों से कीमत कटौती के प्रभाव बन रहे थे, जिससे वस्तुतः घरेलू उद्योग अपनी कीमतें बढ़ाने से रुक गया। घरेलू उद्योग पाटित आयातों की पहुँच कीमत के आधार पर, न कि उचित कीमत पद्धति के आधार पर अपनी कीमतें निर्धारित करने की प्रतिकूल स्थिति में आ गया ताकि वह लागत की वसूली कर सके और उचित लाभ भी प्राप्त कर सके। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की कीमत क्षमताओं तथा निष्पादन पर गंभीर कीमत प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित है जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- ज. नकद हानियों के अलावा, पीवीआईटी, आरओसीई, कीमत मानदंडों संबंधी वृद्धि आदि भी नकारात्मक रहे जो प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटन के कारण है और यह स्थिति अक्षुण्ण रूप से जारी है।
- झ. रोजगार का स्तर उत्पादन में आंशिक वृद्धि के अनुरूप आंशिक रूप से बढ़ा। इस संबंध में यह अनुरोध है कि यदि बाजार में सही स्थिति स्थापित हो जाए और घरेलू उद्योग सामान्य स्तरों पर अपने संयंत्र संचालित करने में सक्षम हो तो घरेलू उद्योग में और अधिक लोगों को रोजगार देने की क्षमता है।
- ञ. साथ ही उत्पादकता एवं मजदूरी प्रति यूनिट क्रमशः सुधार एवं वृद्धि दर्शाते हैं। तथापि, इन वर्षों में मजदूरी में वृद्धि को असामान्य (100 से 128 बिंदु) के रूप में नोट नहीं किया जा सकता तथा भूमि के मजदूरी कानून के अनुसार इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दावा की गई क्षति कंपनी द्वारा दी गई किसी असामान्य मजदूरी के कारण है।
- ट. आरओसीई की स्थिति घरेलू उद्योग के लिए भारी चिंता रही है क्योंकि वह काफी नकारात्मक है जिसका यह मतलब है कि कंपनी द्वारा किए गए निवेश लाभ नहीं दे रहे हैं और उससे वास्तविक क्षति जो हो रही है, के अलावा कंपनी की दीर्घावधि संभावनाएं भी वस्तुतः प्रभावित हो रही हैं।
- ठ. कंपनी की वृद्धि सभी प्रमुख मानदंडों के संबंध में नकारात्मक रही है, यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को वृद्धि की दृष्टि से भी वास्तविक क्षति हुई है।
- ड. इस स्थिति में सूचना यह दर्शाती है कि यद्यपि उत्पादन मात्रा, क्षमता उपयोग, बिक्री और बाजार हिस्सा जैसे कुछ क्षति संबंधी संकेतकों के बाद कुछ आंशिक वृद्धि हुई, परंतु समग्र स्थिति में सभी मानदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति अर्थात् लाभप्रदता, निवेश पर आय, नकद लाभ आदि जांच की अवधि के दौरान काफी नकारात्मक रहे हैं। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से उत्पादकों एवं निर्यातकों द्वारा अपनाए गए आक्रामक पाटन तथा वास्तविक क्षति के स्थिति संबंधी बिंदुओं के कारण वित्तीय हानियां हुई हैं।
- ढ. उपर्युक्त विभिन्न आर्थिक मानदंडों के वस्तुपरक एवं अनुकूल मूल्यांकन स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और उसे मात्रा एवं कीमत मानदंडों दोनों में देखा जा सकता है। पाटित आयातों का कीमत प्रभाव भी काफी रहा है जिसे हानियों कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत ह्रास के संदर्भ में देखा जाता है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता नष्ट हुई तथा घरेलू उद्योग विभिन्न मानदंडों में नकारात्मक आय तथा नकारात्मक वृद्धि वाला हो गया।
- ण. इस प्रकार, क्षति का विश्लेषण स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है तथा पाटित आयातों से यह क्षति बढ़ी है।
- त. निर्यातकों ने यह तर्क दिया है कि (i) याचिकाकर्ता पाटन एवं क्षति दर्शाने के लिए कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं लाए हैं तथा मामले को इस कारण से रद्द किया जाना चाहिए, (ii) इस याचिका में स्पष्ट रूप से कानूनी एवं वास्तविक आधार की कमी है, (iii) याचिकाकर्ता ने आयात की मात्रा को जानबूझकर अत्यधिक बढ़ाया है तथा जानबूझकर क्षति दर्शाई है और (iv) क्षति के दावों का कोई आधार नहीं है। याचिकाकर्ता इन सभी तर्कों को अपने हित में तथा किसी औचित्य के विरोध के रूप में नकारते हैं। यह अनुरोध है कि याचिका में पाटन की प्रथम दृष्टया

मौजूदगी है तथा परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और यह सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई है एवं विभिन्न सूचना के स्रोतों को देकर तथ्यों को बढ़ाकर भी उस पर विश्वास किया गया है। इस प्रकार, प्राधिकारी के पास एक विस्तृत जांच करने के लिए वर्तमान जांच की शुरुआत का औचित्य दर्शाने के लिए पर्याप्त सूचना थी। इस प्रकार, जांच की शुरुआत और वर्तमान जांच सभी कानूनी एवं वास्तविक अपेक्षाओं को पूरा करती है। संबद्ध सामानों से संबंधित आयात आंकड़े डीजीसीआईएंडएस के अनुसार उपलब्ध हैं और घरेलू उद्योग द्वारा उन पर विश्वास किया गया है तथा उसके लेन-देन वार व्यौरे विरोधी पक्षकारों को भी दिए गए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा शामिल किए गए एक भी लेन-देन का गलत रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। किसी भी तरह यह स्पष्ट है कि 2014-15 में आयात अत्यधिक होने के नाते अत्यधिक मांग के अनुरूप था तथा वह जांच की अवधि में कम हो गया, परंतु आधार वर्ष में उसमें वृद्धि हुई। इस प्रकार, ऐसी कोई बात नहीं है जो यह बताये कि डीजीसीआईएंडएस के अनुसार आयात आंकड़े गलत नहीं हैं।

- थ. निर्यातकों ने दावा किया है कि याचिका में जांच की शुरुआत को औचित्यपूर्ण बताने के लिए पाटन और/अथवा क्षति के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं और यह कहा कि संबद्ध देशों से आयात में गिरावट आई है। इन तर्कों को नकारा जाता है क्योंकि वे वास्तविक रूप से गलत हैं। वर्तमान मामले में क्षति की अवधि का आधार वर्ष 2012-13 है और उपर्युक्त आधार वर्ष तथा जांच की अवधि के बीच तुलना की जानी है। निर्यातक ने सुविधापूर्ण रूप से 2014-15 लिया जो कि तत्काल पूर्व वर्ष है जो कि आधार वर्ष के रूप में यह कहने के लिए है कि आयात में गिरावट आई है। यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों से आयात आधार वर्ष में पूरे तौर पर बढ़े हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान आंकड़ों के अनुसार, आयातों में कुछ वृद्धि हुई और उसके बाद जांच की अवधि में आयात कम हुए। यह स्थिति यह नहीं दर्शाती कि आयात नगण्य थे अथवा आयात कम हुए, जैसा कि निर्यातक द्वारा बताया गया है। संबद्ध देशों से आयात कानून विनिर्धारित किए गए अनुसार पाटित कीमतों पर न्यूनतम स्तर से अधिक थे तथा आधार वर्ष में 2319 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच की अवधि में 3501 मीट्रिक टन तक हो गए जो कि स्पष्ट वृद्धि दर्शाते हैं, इस प्रकार निर्यातक का दावा रद्द किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि, वर्तमान मामले में संचयी मूल्यांकन संगत है, अतः टर्की से आयातों में कमी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी टर्की से आयात, जो कुल आयात के 3 प्रतिशत के कानूनी स्तर से काफी अधिक था, पाटित कीमतों पर था। इस प्रकार, टर्की से आयातों से भी घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और वर्तमान जांच के क्षेत्र में उसे बहुत ही सही रूप में शामिल किया गया है।
- द. निर्यातकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री लगभग समान रही है और घरेलू उद्योग ने उस समय कमजोर तरीके से निष्पादन किया, जब मांग अधिक थी। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण ढीली-ढाली रही। जब 2014-15 में मांग उच्चतम थी, तो मांग में पाटित आयातों का हिस्सा भी 69.50 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर था जो कि आधार वर्ष में 31 प्रतिशत था। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग का हिस्सा आधार वर्ष में 44 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 26.58 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार, घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण मांग में इस वृद्धि का लाभ नहीं लिया।
- ध. निर्यातकों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और आयातों की पहुँच कीमत के बीच कोई सह संबंध नहीं है और इसी कारण उन्होंने उल्लेख किया है कि जांच की अवधि में पहुँच कीमत में गिरावट आई है जबकि बिक्री कीमत बढ़ी है। यहां यह नोट किया जाता है कि निर्यातक द्वारा यह समानता सही नहीं है। यद्यपि पहुँच कीमत में गिरावट आई, तथापि, जांच की अवधि के दौरान पहुँच कीमत सकारात्मक कीमत कटौती प्रभाव बना रहे थे जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ऐसे पाटित आयातों की पहुँच कीमत के अनुरूप अपनी कीमतें रखने के लिए मजबूर था जिससे घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ा जिसे घरेलू उद्योग को हुई हानियों में देखा जाता है।
- न. निर्यातकों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री में अत्यधिक कमी नहीं आई है जबकि याचिकाकर्ता का निर्यात निष्पादन अत्यधिक कम हुआ है। यह अनुरोध है कि इस तर्क का क्षति के दावों से कोई संदर्भ नहीं है। दावा की गई क्षतियों का संबंध केवल घरेलू प्रचालन से है। याचिकाकर्ता द्वारा निर्यात बहुत सामान्य थे और निर्यात हानियों में नहीं थे। इस प्रकार, निर्यातकों के इस तर्क कि क्षति निर्यातों में कमी के कारण है, का कोई आधार नहीं है।
- प. निर्यातकों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जांच की अवधि तक बढ़ा है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि पाटित आयातों का बाजार हिस्सा लगभग 48 प्रतिशत रहा है जो घरेलू उद्योग से अधिक था। भारतीय बाजार में पाटित आयातों के इतने बड़े हिस्से से घरेलू उद्योग अपने उत्पाद के लिए अच्छी कीमत और हिस्सा प्राप्त नहीं कर पाया तथा परिणामस्वरूप उसे वास्तविक क्षति हुई। इस प्रकार, बाजार हिस्से में वृद्धि से घरेलू उद्योग का समग्र सकारात्मक निष्पादन सुनिश्चित नहीं हो पाया।

- फ. निर्यातकों ने यह तर्क दिया है कि क्षति का एक प्रमुख कारण कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि तथा मजदूरी में वृद्धि है। यह तर्क किसी भी सत्य से परे है। रोजगार का स्तर उत्पादन में आंशिक वृद्धि के अनुरूप आंशिक रूप से बढ़ा। इस संबंध में यह अनुरोध है कि यदि बाजार में उचित स्थिति स्थापित की जाए और घरेलू उद्योग सामान्य स्तरों पर अपना संयंत्र संचालित करने में सक्षम हो तो घरेलू उद्योग के पास अधिक रोजगार देने की क्षमता है। साथ ही, उत्पादकता और मजदूरी प्रति यूनिट भी सुधार दर्शाते हैं। तथापि, इन वर्षों में मजदूरी में वृद्धि को असामान्य नोट नहीं किया जा सकता और वह भूमि के मजदूरी कानून के अनुसार है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि दावा की गई क्षति कंपनी द्वारा दी गई किसी असामान्य मजदूरी अथवा रोजगार में वृद्धि के कारण है। साथ ही, यह दावा करना आधारहीन है कि उस समय कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई जब क्षमता समान थी। रोजगार उत्पादन से संबंधित है तथा कंपनी क्षमता उपयोग के इस स्तर पर और अधिक लोगों को रोजगार भी दे सकती थी।
- ब. निर्यातकों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग बढ़ा है। ये दावे भ्रामक हैं। उत्पादन में थोड़ी सी वृद्धि के बाद भी क्षमता उपयोग जांच की अवधि के दौरान 56 प्रतिशत रहा जो कि अनुकूलतम से कम स्तर है तथा भारत में उत्पाद के लिए बताई गई मांग का उपयुक्त स्तर नहीं है। घरेलू उद्योग क्षमता उपयोग के इस निम्न स्तर पर बना नहीं रह सकता।
- भ. निर्यातकों ने माना है कि पूरी क्षति की अवधि में कीमत कटौती नकारात्मक रही है। इस संबंध में यह अनुरोध यह कि निर्यातक की अवधारणा सही नहीं है। संबद्ध देशों से जांच की अवधि में कीमत कटौती सकारात्मक रही है।
- म. निर्यातकों ने यह तर्क दिया है कि चूंकि, घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता बढ़ाई है, अतः घरेलू उद्योग के सामने पूंजीगत निवेश बढ़ाने के लिए क्षमता संबंधी कोई मुद्दा नहीं है। यह तर्क वास्तविक रूप से सही नहीं है। घरेलू उद्योग ने क्षमता नहीं बढ़ाई और क्षमता पूरी अवधि में समान रही। घरेलू उद्योग उस स्थिति में कोई भारी निवेश करने की योजना नहीं बना सकता, जब पाटन और क्षति अक्षुण्ण रूप से जारी हो।
- य. निर्यातकों ने यह तर्क दिया है कि एक उत्पादक अर्थात् बालाजी अमीन्स लिमिटेड अच्छा चल रहा है और उपर्युक्त कारणों से विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद के बीच लागत आबंटन की जांच की जानी चाहिए। यह अनुरोध है कि निर्यातक की यह बात उचित नहीं है तथा याचिकाकर्ताओं को प्राधिकारी द्वारा आंकड़ों की जांच की किसी मात्रा पर कोई आपत्ति नहीं है। विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद के बीच लागत के आबंटन का आधार स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है और निर्यातक की स्थितियां अधिकृत नहीं हैं। साथ ही, पाटनरोधी योजना अपने आप में उत्पाद विशिष्ट है और जो संगत है, वह समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन है न कि याचिकाकर्ता कंपनी का समग्र निष्पादन।
- कक) निर्यातकों ने तर्क दिया है कि एनआईपी के प्रयोजन के लिए 22 प्रतिशत आरओआई औचित्यपूर्ण नहीं है। हम निर्यातक के सभी दावों को किसी औचित्य से परे मानते हुए नकारते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी निरंतर कई मामलों में ऐसी परिपाटियां लागू करते आए हैं तथा वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए भी इसी दृष्टिकोण की आवश्यकता है तथा कम से कम 22 प्रतिशत अनिवार्य है। किसी भी मंच द्वारा ऐसे निर्णय नहीं दिए गए हैं जो यह बताएं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी एनआईपी के प्रयोजन के लिए 22 प्रतिशत आरओआई लागू नहीं कर सकते। इसके विपरीत, माननीय सेसटेट द्वारा बताई गई न्यायिक स्थिति यह है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी की 22 प्रतिशत लागू करने की परिपाटी संगत है तथा इसमें कुछ भी अनुचित नहीं पाया गया है।
- खख) टर्की दूतावास के इस दावे के संबंध में कि संबद्ध सामानों का आयात कम हुआ है और ऐसे आयात के कारण कोई क्षति नहीं हुई है, यह अनुरोध है कि आयात में कमी क्षति को नहीं नकारती। इस प्रकार की गिरावट के बाद भी टर्की से आयात की मात्रा कुल आयातों में लगभग 18 प्रतिशत थी जबकि शुरूआती स्तर पर पाटनरोधी करार के अनुसार ही केवल 3 प्रतिशत है। टर्की से आयात पाटित कीमतों पर भी थे। इस प्रकार, टर्की से आयातों ने भी घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान किया और वर्तमान मामले में वास्तविक तथ्य क्षति के संचयी मूल्यांकन के लिए आवश्यक हो जाते हैं।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

37. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.1 तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों संबंधी पाटित आयातों के प्रभाव तथा पाटित आयातों की मात्रा; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव, दोनों की वस्तुपरक जांच का प्रावधान है। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है, पूर्ण रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती हुई है अथवा ऐसे आयातों का

प्रभाव अन्यथा काफी मात्रा में कीमत के न्यूनीकरण के लिए है, अथवा इससे कीमतों में वृद्धि पर रोक लगती है, जो काफी मात्रा में हुई होती।

38. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में निम्नलिखित उल्लेख है:

*"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का मूल्यांकन शामिल है, जिनमें लाभ, आउटपुट, मार्केट शेयर, उत्पादकता, निवेश पर वापिसी या क्षमता का उपयोग, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, वास्तविक पाटन मार्जिन की मात्रा और नकदी प्रवाह पर संभावित ऋणात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, संवृद्धि, पूंजीगत निवेशों को जुटाने की क्षमता सम्मिलित है।"*

39. प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया क्षति विश्लेषण यथा तथ्यतः विरोधी हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग द्वारा भी किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए कुछ विशिष्ट अनुरोधों का प्राधिकारी का दौरा निम्नलिखित रूप में समाधान किया गया है:

- क. इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए स्थिति सिद्ध करने हेतु कोई पर्याप्त साक्ष्य उल्लिखित नहीं किए हैं, यह नोट किया जाता है कि जांच की शुरुआत के औचित्य के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर वर्तमान जांच शुरू की गई थी।
- ख. इस तर्क के संबंध में कि जांच के लिए तथा डीएमएसी के आयातों पर पाटनरोधी उपाय लगाए जाने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन में कानूनी एवं वास्तविक आधार की कमी है, यह नोट किया जाता है कि यह मामला आवेदन पत्र में दिए गए साक्ष्यों के प्रथम दृष्टया मूल्यांकन के आधार पर शुरू किया गया था।
- ग. इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता के दावे प्रकाशित सूचना के विपरीत हैं तथा ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को क्षति दर्शाने के लिए वे बनावटी हैं, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने क्षति से संबंधित केवल उसी सत्यापित सूचना पर विचार किया जो संबद्ध सामानों के लिए संगत है।
- घ. इस तर्क के संबंध में कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में टर्की का समर्पित कोड है, भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात कम हुआ है और ऐसे परिदृश्य में टर्की से आयात भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि का कारण नहीं है, यह नोट किया जाता है कि टर्की से आयात भारत में कुल आयातों में लगभग 18 प्रतिशत रहा है जो कि सकारात्मक पाटन मार्जिन है तथा ऐसे परिदृश्य में टर्की के विरुद्ध जांच कानून के अनुसार अपरिहार्य थी।
- ङ. इस तर्क के संबंध में कि भारत टर्की के विरुद्ध व्यापार अधिशेष का हमेशा लाभ लेता रहा है जो कि वार्षिक रूप से 5-6 बिलियन की दर पर है, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच का विचाराधीन उत्पाद के पाटन तथा भारत में समान वस्तु का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच का सीमित क्षेत्र है।
- च. इस तर्क के संबंध में कि वर्तमान मामले में कोई संचयी मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए और चीन एवं टर्की से आयातों के प्रभाव की अलग से जांच की जानी चाहिए। यह नोट किया जाता है कि इस प्रकटन विवरण में उपयुक्त स्थानों पर विस्तारपूर्वक दिए गए कारण से वर्तमान मामले में संचयी मूल्यांकन औचित्यपूर्ण है।
- छ. इस तर्क के संबंध में कि क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने विभिन्न मानदंडों के संबंध में सकारात्मक प्रवृत्तियां दर्शाई हैं तथा यह कि बाजार हिस्सा, बिक्री, उत्पादन, क्षमता, उत्पादकता, लाभ, निवेश आदि की दृष्टि से प्रवृत्ति सकारात्मक रही है, इस प्रकटन विवरण में की गई क्षति की जांच में यथा तथ्यतः अनुरोधों का समाधान कर दिया गया है।
- ज. इस तर्क के संबंध में कि टर्की से आयातों से कोई क्षति न होने के मद्देनजर भारतीय प्राधिकारी को पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.2 तथा भारतीय पाटनरोधी कानूनों के अनुरूप कार्य करना चाहिए जिससे वर्तमान मामला रद्द हो जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि यह मुद्दा इस प्रकटन विवरण में संगत स्थानों पर ले लिया गया है।
- झ. विभिन्न चरणों में घरेलू उद्योग द्वारा दायर आंकड़ों में विसंगति के मुद्दे के संबंध में घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि जांच की शुरुआत के दौरान दायर किए गए आंकड़े 15 वर्षों के लिए थे और जांच की शुरुआत के बाद के आंकड़े जांच की शुरुआत के लिए थे जो 18 माह के लिए थे तथा अवधि में इस प्रकार के परिवर्तन के कारण सूचीबद्ध आंकड़ों में परिवर्तन हुआ।
- ञ. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि यद्यपि याचिका दायर करते समय आरसीएफ ने ईओयू को निर्यात के रूप में बिक्री को माना और तदनुसार ऐसी बिक्री की मात्रा तथा मूल्य को निर्यात के रूप में माना गया, परंतु बाद में ईओयू को इस प्रकार की सभी बिक्रियां घरेलू बिक्री के रूप में मानी गईं क्योंकि इसे लागत लेखा

परीक्षा रिपोर्ट में उस प्रकार माना गया तथा इसीलिए इस प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव बिक्री की मात्रा पर तथा कीमत संबंधी सभी मानदंडों पर पड़ा। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण विश्वसनीय लगने वाला प्रतीत होता है।

- ट. जहां तक बालाजी अमीन्स का संबंध है, याचिकाकर्ता ने अपने लिखित अनुरोध में स्वीकार किया कि क्षमता की सूचना देने के संबंध में कंपनी की ओर से गलती हुई थी। पूरी क्षति की अवधि के दौरान वास्तविक क्षमता 2500 मीट्रिक टन थी और उसका साक्ष्य कंपनी के स्थान पर स्थल सत्यापन के दौरान प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया था। जहां तक जांच की अवधि के लिए लागत और कीमत का संबंध है, वह जांच की शुरुआत के समय अनंतिम रूप से प्रस्तुत की गई थी तथा इस समय आंकड़े प्राधिकारी द्वारा सत्यापित आंकड़ों के अनुसार हैं।

### **संचयी मूल्यांकन**

40. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि जहां एक से अधिक देश से उत्पाद के आयात पाटनरोधी जांचों के अध्यक्षीन साथ-साथ रखे जा रहे हों, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करेंगे, यदि वह निर्धारित करता है कि:

- क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सिद्ध पाटन का मार्जिन 2 प्रतिशत से अधिक निर्यात की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के 3 प्रतिशत (अथवा अधिक) है अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात 3 प्रतिशत से कम है, आयात सार्वजनिक रूप से समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक के लिए होता है, और
- ख. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्द्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।

41. प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करते हैं कि:

- क. संबद्ध सामान संबद्ध देशों से भारत में पाटित किए जा रहे हैं। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन के मार्जिन नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक हैं।
- ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अलग-अलग आयातों की कुल मात्रा के 3 प्रतिशत से अधिक है।
- ग. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात केवल उनमें से प्रत्येक द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं के साथ सीधे ही प्रतिस्पर्द्धा नहीं करते बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।
- घ. टर्की से आयात में कमी को टर्की के लिए अलग से विश्लेषण करने हेतु कारक के रूप में नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार की गिरावट के बाद भी टर्की से आयात महत्वपूर्ण स्तरों पर रहे और टर्की से आयात भी पाटित कीमतों पर थे।

42. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति का मूल्यांकन संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के निर्यात से संचयी रूप से करना उपयुक्त होगा।

### **ii. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव**

#### **क. मांग और बाजार हिस्सा**

43. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए सभी स्रोतों से आयातों तथा सभी भारतीय उत्पादकों द्वारा समान वस्तु की घरेलू बिक्री की राशि के रूप में भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत परिभाषित की है। प्राधिकारी ने सभी स्रोतों से भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा और मूल्य निर्धारित करने के लिए डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन वार आयात आंकड़ों के अनुसार भारत में आयातों पर विचार किया है। इस प्रकार मूल्यांकित मांग निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

#### **(i) मांग**

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई(वार्षिकीकृत)
मांग	मी. टन	7,458	8,041	9,915	7,912
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100	108	133	106

संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	2,319	2,930	6,891	3,501
अन्य देशों से आयात	मी. टन	1,854	1,930	389	648
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	3,284	3,180	2,635	3,763

## (ii) मांग में घरेलू उद्योग और आयात का बाजार हिस्सा

44. विभिन्न स्रोतों से संबद्ध सामानों के आयात और भारतीय उत्पादकों के संबद्ध सामानों की बिक्री पर विचार करते हुए मांग निर्धारित की गई थी और इसके अतिरिक्त, संबद्ध आयातों, घरेलू उद्योग और भारत में इस मांग में अन्य आयातों के बाजार हिस्सा की भी जांच की गई और इस संबंध में वास्तविक स्थिति निम्नलिखित है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई (वार्षिकीकृत)
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	44.04	39.56	26.58	47.55
संबद्ध देशों से आयात	%	31.10	36.44	69.50	44.25
अन्य देशों से आयात	%	24.86	24.00	3.92	8.19

45. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में उत्पाद के लिए मांग ने आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाई है, परंतु पिछले दो वर्षों में मांग की तुलना में गिरावट दर्शाई है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा, जो आधार वर्ष में 44.04 प्रतिशत था, वह 2014-15 में घटकर 26.58 प्रतिशत हो गया, परंतु जांच की अवधि में बढ़कर पुनः 47.55 प्रतिशत हो गया। संबद्ध देशों से आयातों के हिस्से में वृद्धि आधार वर्ष में 31.10 प्रतिशत से बढ़कर जांच की अवधि में 44.25 प्रतिशत हो गई। तथापि, यह पिछले वर्ष में 69.50 प्रतिशत के हिस्से की तुलना में कम था।

## ख. संबद्ध देशों की आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

46. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में, पूर्ण रूप में अथवा उत्पादन की तुलना में अथवा भारत में खपत की दृष्टि से काफी वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात की मात्रा का इस संबंध में निम्नलिखित रूप में विश्लेषण किया गया है।

47. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस द्वारा दिए गए लेन-देन वार आयात आंकड़ों के अनुसार संबद्ध सामानों के आयात की मात्रा की जांच की है। रिकार्ड में उपलब्ध इन आयात आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक देश से आयात की मात्रा न्यूनतम स्तरों से अधिक पाई गई है। संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयात की मात्रा निम्नलिखित रही है:

विवरण		यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई (वार्षिकीकृत)
मात्रा	चीन जन गण	मी. टन	654	1549	6344	2731
	टर्की	मी. टन	1,666	1,381	547	770
	संबद्ध देश कुल	मी. टन	2,319	2,930	6,891	3,501
	अन्य देश	मी. टन	1,854	1,930	389	648
	कुल आयात	मी. टन	4,173	4,860	7,280	4,149
आयातों में बाजार हिस्सा	चीन जन गण	%	15.66	31.88	87.14	65.83
	टर्की	%	39.91	28.41	7.52	18.55
	संबद्ध देश	%	55.58	60.29	94.66	84.38
	अन्य देश	%	44.42	39.71	5.34	15.62



48. संबद्ध देशों से आयात, जो आधार वर्ष में 2319 मी. टन थे, वे बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 3501 मी. टन हो गए। तथापि, वह तत्काल पिछले वर्ष में 6891 मी. टन की आयात मात्रा से काफी घट गए हैं। इस प्रकार कोई स्पष्ट प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती।

49. जहां तक 2014-15 के दौरान आयातों में असामान्य वृद्धि का संबंध है, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग औसत उद्योग में घोल अथवा प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। डीएमएसी की प्रमुख खपत अरविन्दो फार्मा, कोवालर्ट लेबोरेट्रीज, डेविस लेबोरेट्रीज, आर्किट केमिकल्स आदि द्वारा उत्पादित सेफोरेक्साइम एक्सेटिल नामक औषधि में है। वर्ष 2014-15 के दौरान और इस एंटीबायोटिक की असामान्य मांग भारत और विदेश दोनों जगह थी और इसीलिए डीएमएसी के लिए मांग उस वर्ष विशेष में काफी बढ़ी तथा परिणामस्वरूप वर्ष 2014-15 के दौरान इन कंपनियों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का आयात बढ़ा। याचिकाकर्ता का उपर्युक्त तर्क डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन वार आंकड़ों से सत्यापित किया गया था और यह पाया गया था कि इन फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने 2015-16 में आयात के \*\*\* मी. टन की तुलना में वर्ष 2014-15 में विचाराधीन उत्पाद के \*\*\* मी. टन का आयात किया।

#### ग. उत्पादन और खपत की तुलना में पाटित आयातों का हिस्सा

50. उत्पादन और खपत की तुलना में पाटित आयातों के हिस्से से संबंधित संगत सूचना नीचे देखी जा सकती है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई (वार्षिकीकृत)
संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	2,319	2,930	6,891	3,501
घरेलू उद्योग का उत्पादन	मी. टन	3,410	3,149	2,879	4,025
घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में संबद्ध देश से आयात	%	68.01	93.05	239.35	87.00
भारत में खपत की तुलना में संबद्ध देश से आयात	%	31.10	36.44	69.50	44.25

51. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात पूर्ण रूप से बढ़े हैं और 2014-15 तक भारत में उत्पादन एवं खपत की तुलना में भी बढ़े हैं तथा फिर उन्होंने गिरावट दर्ज की।

#### i. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

52. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, नियमावली के अनुबंध-II(ii) में निम्नलिखित निर्धारित है:

“जहां तक नियम 18 के उप नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।”

53. इसकी जांच की गई है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत के पाटित आयातों द्वारा कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का न्यूनीकरण करने के लिए अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए अन्यथा है, जो कि अन्यथा काफी मात्रा तक हुआ होता। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए उत्पादन की भारित औसत लागत (सीओपी), घरेलू उद्योग की भारित औसत निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) की तुलना निम्नलिखित उचित खंडों में संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच लागत से की गई है।

#### क) कीमत कटौती

54. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने आयातों की पहुँच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से की है। इस संबंध में, उत्पाद के पहुँच मूल्य तथा घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच सभी छूटों और करों का निवल के व्यापार के उसी स्तर पर तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें कारखानागत स्तर पर निर्धारित की गई थीं। घरेलू कीमतें और कटौती का मार्जिन निम्नलिखित तालिका के अनुसार दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	चीन जन गण	टर्की	संबद्ध देश
पहुँच मूल्य	रु./कि. ग्रा.	75.57	77.89	76.08
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./कि. ग्रा.	***	***	***
कीमत कटौती	रु./कि. ग्रा.	***	***	***
कीमत कटौती	%	0-5	नकारात्मक	0-5

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि में संबद्ध देशों से कीमत कटौती आंशिक रूप से सकारात्मक रही है।

#### ख) कीमत न्यूनीकरण/ह्रास

56. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से काफी मात्रा में कीमतों का न्यूनीकरण हो रहा है अथवा कीमतों में वृद्धि पर रोक लग रही है जो कि अन्यथा काफी मात्रा तक हो गया होता, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में लागत एवं कीमतों में परिवर्तनों की जांच की। वास्तविक स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई(वार्षिकीकृत)
उत्पादन की लागत	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	136	129
बिक्री कीमत	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	114	103
पहुँच मूल्य (संबद्ध देश)	रु./कि. ग्रा.	81.39	85.73	83.66	76.08
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	103	93

57. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि उत्पादन लागत आधार वर्ष में 100 सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि में 129 अंक तक हो गई, जबकि बिक्री कीमत आधार वर्ष में 100 सूचकांक से जांच की अवधि में 103 सूचकांक तक हो गई। उसी अवधि में संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत आधार वर्ष में 100 सूचकांक से घटकर जांच की अवधि में 93 अंक हो गई जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से आयातों के पहुँच मूल्य के बराबर करने के लिए बिक्री कीमत कम की थी। कीमत न्यूनीकरण इस तथ्य से सिद्ध है कि घरेलू उद्योग लागतों में वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमतें नहीं बढ़ा सका। जांच की अवधि के दौरान कीमत न्यूनीकरण भी सिद्ध है।

#### छ. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

58. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है:-

#### क. क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग

59. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई (वार्षिकीकृत)
क्षमता मी. टन	मी. टन	7,500	7,500	7,500	7,500
उत्पादन	मी. टन	3,410	3,149	2,879	4,025
क्षमता उपयोग	%	45.47	41.99	38.39	53.66

60. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की क्षमता पूरी क्षति की अवधि में समान रही है और घरेलू उद्योग का उत्पादन तथा क्षमता उपयोग क्षति की अवधि के दौरान तथा जांच की अवधि में भी बढ़ा है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि वृद्धि के बाद भी क्षमता उपयोग 53.66 प्रतिशत रहा है, जिसका घरेलू उद्योग द्वारा कम अनुकूलतम स्तर होने का दावा किया गया है।

61. विरोधी पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने स्वीकार्य रूप से लिखित अनुरोध के समय बाद में कुल क्षमता उपयोग परिवर्तित किया। प्राधिकारी ने इस संबंध में याचिकाकर्ता के दावों को जांच एवं सत्यापन के अधीन रखा है और वे यह पाते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित क्षमता 7500 मी. टन प्रति वर्ष है।

#### ख. बिक्री मात्रा और बाजार हिस्सा

62. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा और बाजार हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई (वार्षिकीकृत)
घरेलू बिक्री	मी. टन	3,284	3,180	2,635	3,763
मांग	मी. टन	7,458	8,041	9,915	7,912
मांग घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	44.04	39.56	26.58	47.55

63. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री ने आधार वर्ष में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि दर्शाई है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि घरेलू उद्योग की वृद्धि से अधिक रही है।

#### ग. मालसूची

64. घरेलू उद्योग में औसत स्टॉक के रूप में नोट की गई मालसूची की स्थिति निम्नलिखित हो गई:

	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई (वार्षिकीकृत)
औसत स्टॉक	मी. टन	39	27	114	367

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का मालसूची स्तर जांच की अवधि में बढ़ा है, परंतु यह लगभग एक माह की आवश्यकता के बराबर है।

#### घ. लाभ/हानि

66. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई (वार्षिकीकृत)
लाभ	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(167)	(2767)	(3284)
लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(161)	(2220)	(3762)

67. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध सामानों के संबंध में वित्तीय हानियां हो रही हैं तथा जांच की अवधि के दौरान ये हानियां अधिकतम थीं।

#### ङ. नियोजित पूंजी पर लाभ

68. नियोजित पूंजी पर लाभ के संबंध में सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई (वार्षिकीकृत)
व्याज और कर पूर्व लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
नियोजित पूंजी	रु. लाख	***	***	***	***
नियोजित पूंजी पर लाभ	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(53)	(4563)	(7775)

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का नियोजित पूंजी पर लाभ जांच की अवधि के दौरान सहित क्षति की पूरी अवधि में नकारात्मक रहा है। यद्यपि, आरओआई आधार वर्ष में आंशिक रूप से नकारात्मक था, तथापि, वह जांच की अवधि में काफी नकारात्मक हो गया है।

#### च. नकदी प्रवाह

70. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के नकद प्रवाह की स्थिति पर पाटन के प्रभाव की जांच करने के लिए नकद प्रवाहों में प्रवृत्तियों की जांच की है। घरेलू उद्योग के नकद लाभ के संबंध में सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई (वार्षिकीकृत)
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	(603)	(1,251)

71. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का नकद लाभ क्षति की अवधि में घटा है और आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में नकारात्मक रहा है।

#### छ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

72. संबद्ध देशों से आयात की कीमतों, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्द्धा, घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों आदि की जांच यह दर्शाती है कि बिक्री कीमतों में घटती हुई आयात कीमतों के कारण लागत में वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है जिससे कीमत न्यूनीकरण हुआ है।

#### ज. उत्पादकता

73. उत्पादकता के संबंध में सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई (वार्षिकीकृत)
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन/सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	77	94
प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	84	118

74. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की प्रति कर्मचारी उत्पादकता आधार वर्ष में आंशिक रूप से कम हुई है। तथापि, वह तत्काल पिछले वर्ष में बढ़ी है।

#### झ. रोजगार और मजदूरी

75. रोजगार एवं मजदूरी के संबंध में सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई (वार्षिकीकृत)
कर्मचारी	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	110	125
मजदूरी	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	137	128

76. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का रोजगार स्तर क्षति की अवधि में और जांच की अवधि के दौरान बढ़ा है। मजदूरी प्रति किलोग्राम में भी आधार वर्ष में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है तथा तत्काल पिछले वर्ष में कमी आई है।

#### ब. वृद्धि

77. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की वृद्धि प्रमुख मानदंडों की संख्या में नकारात्मक रही है। यह नकारात्मक वृद्धि उस समय देखी जा सकती है जब उत्पाद के लिए मांग ने सतत वृद्धि दर्शाई है।

#### ट. पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग में वर्तमान में भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता है तथा पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता का प्रश्न संभावित निवेशों के लिए संगत होगा।

#### ठ. पाटन और पाटन मार्जिन का स्तर

79. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर आ रहे हैं और पाटन के मार्जिन काफी हैं।

#### ज. क्षति संबंधी निष्कर्ष

80. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन काफी है। पाटित आयातों का कीमत न्यूनीकरण के संदर्भ में प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ा है। पाटित आयातों के प्रभाव से घरेलू उद्योग लागतों में वृद्धि के अनुरूप संबद्ध सामानों की कीमतें बढ़ाने से रुक गया जिससे वित्तीय हानियां हुईं।

81. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग जैसे मात्रात्मक मानदंड जांच की अवधि तक बढ़े हैं। यद्यपि, क्षमता उपयोग लगभग 54 प्रतिशत रहा तथा मालसूची बढ़ी। कीमत मानदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग को नकद हानियां हुई हैं और संबद्ध लाभ मानदंड आरओसीई सहित नकारात्मक रहे हैं। इसे पाटित आयातों से सृजित कीमत न्यूनीकरण के आलोक में देखे जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, संबद्ध देशों से पाटित आयातों से लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय आदि के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हुआ है।

#### झ. क्षति और क्षति मार्जिन की मात्रा

82. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी का निर्धारण जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। घरेलू उद्योग की एनआईपी का निर्धारण संयंत्र-वार किया गया है और तदनुसार, औसत एनआईपी निकाली गई है। इस प्रकार, निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना निम्नलिखित रूप में क्षति मार्जिन निर्धारित करने के लिए संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत के साथ की गई है।

क्रम सं.	देश	उत्पादक	निर्यातक	क्षति रहित कीमत - अमेरिकी डॉलर/मी. टन	पहुँच कीमत - अमेरिकी डॉलर/मी. टन	क्षति मार्जिन - अमेरिकी डॉलर/मी. टन	क्षति मार्जिन - %	क्षति मार्जिन रेंज - %
1	चीन जन गण	हेनन जुनहुआ डेवेलपमेंट कं. लि.	हेनन जुनहुआ डेवेलपमेंट कं. लि.	***	***	***	***	10-20
2	चीन जन गण	झेजियांग जियांगशन केमिकल कं. लि.	झेजियांग जियांगशन केमिकल कं. लि.	***	***	***	***	0-10
3	चीन जन गण	कोई अन्य	कोई अन्य	***	***	***	***	15-25
4	टर्की	कोई अन्य	कोई अन्य	***	***	***	***	0-10

#### ब. कारणात्मक सम्पर्क और अन्य कारक

83. विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों/प्रयोक्ताओं/आयातकों द्वारा किए गए कारणात्मक संपर्क संबंधी अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पादों का कोई पाटन नहीं था और आयातित उत्पादों से भारतीय घरेलू उद्योग को कोई क्षति अथवा क्षति का खतरा नहीं हुआ।
- क्षति, यदि कोई हुई है, रोजगार एवं मजदूरी में वृद्धि के कारण है।

- iii. पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 3.5 यह दर्शाता है कि क्षति का कोई अन्य कारण आयातों को नहीं माना जाना चाहिए। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए निर्यात में स्पष्ट कमी है। साथ ही बढ़ती हुई क्षमता की भी कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच किए जाने की आवश्यकता है।

84. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए कारणात्मक संपर्क संबंधी अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- i. वर्तमान मामले में पाटन काफी है, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और यह क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटन के कारण हुई है।
- ii. यद्यपि याचिका में क्षति न होने का विश्लेषण सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग को क्षति किसी अन्य कारक के कारण नहीं हुई है। तथापि, याचिकाकर्ताओं का अनुरोध है कि निम्नलिखित मानदंड सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।
  - (क) विचाराधीन उत्पाद की जिस कीमत पर भारत में आयात किया गया है, वह सामान्य मूल्य से कम है। परिणामस्वरूप काफी पाटन मार्जिन है।
  - (ख) संबद्ध देशों से पहुँच कीमत पिछले वर्ष तथा आधार वर्ष की तुलना में कम हुई है जिससे घरेलू उद्योग पर कीमत न्यूनीकरण प्रभाव पड़ा।
  - (ग) पाटित कीमत पर आयात की मौजूदगी से घरेलू उद्योग इनपुट लागत में वृद्धि की सीमा तक अपनी कीमत बढ़ाने के लिए रुक रहा है। इस प्रकार, आयातों से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों का न्यूनीकरण हो रहा है।
  - (घ) लाभ में कमी से प्रत्यक्ष रूप से नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ में ह्रास हुआ है और दोनों नकारात्मक हुए हैं। घरेलू उद्योग पूंजी की लागत लेने में सक्षम नहीं रहा है।

85. प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो पाई है। संबद्ध देशों से पाटन और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क की जांच निम्नलिखित रूप में की गई है:

**(क) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमतें**

86. संबद्ध देशों को छोड़कर देशों से आयात मात्रा की दृष्टि से इतने अधिक नहीं हैं कि वे घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकें अथवा खतरा पैदा कर सकें। अन्य देशों से आयात उच्च कीमतों पर थे। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि अन्य देशों से आयातों के कारण क्षति हुई है।

**(ख) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ और प्रतिस्पर्धा**

87. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों के लिए एकल बाजार है जहाँ संबद्ध देशों से पाटित आयात घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए संबद्ध सामानों के साथ सीधे ही प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि आयातित संबद्ध सामान और घरेलू रूप से उत्पादित सामान समान वस्तु हैं तथा उनका प्रयोग समान अनुप्रयोगों/अंतिम प्रयोगों के लिए किया जाता है। विदेशी उत्पादकों तथा घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियों तथा प्रतिस्पर्धा का कोई साक्ष्य नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहा हो।

**(ग) मांग का संकुचन या खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद के लिए मांग क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान भी वृद्धि दर्शाती है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग को क्षति मांग में संकुचन के कारण नहीं थी।

**(घ) प्रौद्योगिकी में विकास**

89. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

**(ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन**

90. घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभावित महत्वपूर्ण ह्रास के कारण नहीं है। अतः निर्यात निष्पादन में कोई भी संभावित गिरावट किसी क्षति के कारण नहीं है।

**(च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता**

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादकता में ह्रास से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

**(छ) अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन**

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन से घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि प्राधिकारी द्वारा विचार में लाई गई सूचना विचाराधीन उत्पाद के संबंध में ही है।

**(ट) कारणात्मक सम्पर्क स्थापित करने वाले कारक**

93. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन की क्षति की अवधि में और जांच की अवधि के दौरान वास्तविक रूप से क्षति हुई है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक सम्पर्क निम्नलिखित आधारों पर सिद्ध किया जाता है:

- क. संबद्ध सामानों का आयात पाटित कीमतों पर था।
- ख. मांग में पाटित आयातों का बाजार हिस्सा जांच की अवधि के दौरान लगभग 44 प्रतिशत रहा है जो कि उपयुक्त रूप से महत्वपूर्ण प्रतिशतता है और उसी से घरेलू उद्योग अधिक उत्पादन और बिक्री करने से रुक गया जो कि ऐसे पाटित आयातों के अभाव में किया जा सकता था।
- ग. घरेलू उद्योग के पास मांग बढ़ने के बावजूद जांच की अवधि में उपयोग में न लाई गई महत्वपूर्ण क्षमता थी।
- घ. संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों पर न्यूनात्मक प्रभाव पड़े हैं।
- ङ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।
- च. इन तथ्यों और विश्लेषण से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

94. जांच की अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एकत्र किए गए और वर्तमान प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा विश्लेषित किए गए अनिवार्य तथ्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किए जा रहे हैं ताकि ये हितबद्ध पक्षकार इन तथ्यों पर अपनी टिप्पणियां दे सकें।

**ठ. प्रकटन विवरण पश्चात हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

95. प्रकटन पश्चात अनुरोध हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए हैं। उनमें उठाए गए अधिकांश मुद्दे जांच के दौरान पहले भी उठाए गए हैं और उनका समाधान उपयुक्त रूप से कर दिया गया है। अतिरिक्त अनुरोधों का विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार किया गया है :

**घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

- i. संपूर्ण क्षति की अवधि के दौरान आयात में वृद्धि हुई और यह जांच की अवधि के दौरान आधार वर्ष की तुलना में अधिक थी और जांच की अवधि में गिरावट केवल तत्काल पूर्व वर्ष की तुलना में हुई जिसके दौरान आयात में कुछ असामान्य वृद्धि फार्मा क्षेत्र में कुछ विशिष्ट मांग के कारण हुई, जैसा कि समझा गया है। इस प्रकार से, आयात में एक समग्र बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गई है जैसा कि आधार वर्ष और जांच की अवधि के बीच तुलना से स्पष्ट है।
- ii. घरेलू उद्योग के संघटकों में से एक संघटक की दावा की गई निवल निर्धारित परिसंपत्ति और उस परिसंपत्ति जिसकी अनुमति प्राधिकारी द्वारा दी गई थी, के बीच असंतुलन है।
- iii. कार्यशील पूंजी की गणना करते समय, प्राधिकारी ने सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी और चालू परिसंपत्ति के रूप में खरीदे गए उत्पादों के माल भंडार की अनुमति नहीं दी है। चूंकि उसकी अनुमति चालू परिसंपत्ति के रूप में नहीं दी गई है अतः अनुरोध है कि प्राधिकारी कंपनी की सब्सिडी की निवल कुल बिक्री और खरीदे गए उत्पादों की निवल बिक्री पर विचार करें।
- iv. प्राधिकारी ने मध्यवर्ती के अंतरण कीमत के रूप में उचित लाभ के साथ डीएमए की लागत पर विचार किया है। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे डीएमए के लिए अंतरण कीमत के रूप में बिक्री कीमत पर विचार करें। यदि कंपनी ने डीएमए प्रस्तुत नहीं किया तब वे उसकी खरीद करने के लिए बाध्य थे। इस कारण से बिक्री कीमत को अंतरण कीमत के रूप में अवश्य लिया जाना चाहिए।

- v. जांच की अवधि में कंपनी का क्षमता उपयोग 92.52% था जो जांच की अवधि और पिछले तीन वर्षों के लिए सबसे अधिक थी। उसके बावजूद निर्धारित खर्चों को सामान्य बनाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने खर्चों के आवंटन में परिवर्तन उसके लिए कोई तर्क दिए बिना किया है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

i) निर्धारित परिसंपत्ति पर लाभ की पुनः जांच की गई है और यह देखा गया है कि जांच की अवधि के दौरान, आर सी एफ लि. का डीएमएसी संयंत्र 253 दिनों के लिए बंद था। उसी प्रकार से जांच की अवधि के दौरान, मै. बालाजी अमाइन्स लि. का डीएमएसी संयंत्र भी लगातार कार्य नहीं कर रहा था और यह माल भंडार के जमा होने से बचने के लिए प्रायः प्रत्येक माह में कुछ दिनों के लिए बंद रहा था। आरसीएफ के उत्पादन की लागत पर विचार यह मानते हुए लेखा परीक्षित लागत लेखाओं के रिकॉर्डों के आधार पर किया गया है कि बेकार समय के दौरान हुए खर्चों पर लेखा परीक्षक द्वारा उपयुक्त रूप से विचार किया गया है। निर्धारित परिसंपत्तियों पर आय की पुनः जांच तदनुसार, कंपनी द्वारा रखे गए रिकॉर्डों के अनुसार किया गया है।

ii) मै. आरसीएफ लि. के लिए, सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी और खरीदे गए उत्पादों का माल भंडार की अनुमति चालू परिसंपत्तियों के रूप में नहीं दी गई है। चूंकि उसकी अनुमति चालू परिसंपत्ति के रूप में नहीं दी गई है अतः कंपनी की कुल बिक्री पर भी विचार सब्सिडी की निवल राशि और खरीदे गए उत्पादों की निवल राशि पर किया गया है।

iii) मै. बालाजी अमाइन्स लि. डीएमए का उत्पादन कर रहा है और उसका उपयोग विचाराधीन उत्पाद (अर्थात् डीएमएसी) के उत्पादन के लिए कैप्टिव खपत के लिए कर रहा है। डीएमए की लागत पर विचार अंतरण कीमत के रूप में किया गया है और उचित लाभ प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई सतत विगत प्रथा के अनुसार दिया गया है।

iv) जांच की अवधि में, मै. बालाजी अमाइन्स लि. का क्षमता उपयोग 92.52%, था जो जांच की अवधि और पिछले तीन वर्षों के लिए सबसे अधिक था। अतः पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के अनुसार प्रति युनिट निर्धारित लागत निकालने के लिए उस पर विचार किया गया है।

तदनुसार, उपर्युक्त के आधार पर संशोधित क्षति मार्जिन नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	देश	उत्पादक	निर्यातक	क्षतिरहित कीमत— अम.डॉ./मी.ट.	पहुंच कीमत— अम.डॉ./मी.ट.	क्षति मार्जिन— अम.डॉ./मी.ट.	क्षति मार्जिन - %	क्षति मार्जिन रेंज - %
1	चीन जन.गण.	हेनान जुनहुआ डेवलपमेंट कं. लि.	हेनान जुनहुआ डेवलपमेंट कं. लि.	***	***	***	***	10-20
2	चीन जन.गण.	झेजियांग जिआनशांग कैमिकल कं. लि.	झेजियांग जिआनशांग कैमिकल कं. लि.	***	***	***	***	0-10
3	चीन जन.गण.	कोई	कोई	***	***	***	***	15-25
4	टर्की	कोई	कोई	***	***	***	***	0-10

### **ड. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे :**

96. प्राधिकारी का यह मानना है कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाने से भारत में इस उत्पाद की कीमत की अटकलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों को लगाने से कम नहीं होगी। इसके प्रतिकूल, पाटनरोधी उपायों को लगाने से पाटन प्रथाओं द्वारा प्राप्त होने वाले अनुचित लाभ को दूर किया जाएगा, घरेलू उद्योग का ह्रास रुकेगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। इस कारण से पाटनरोधी शुल्कों को लगाने से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों को लगाने से किसी भी प्रकार से संबद्ध देशों से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता अब भी आपूर्ति के दो अथवा उससे अधिक स्रोतों को बनाए रख सकते हैं।



**ढ. सिफारिशें**

97. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि

**क.** विचाराधीन उत्पाद का निर्यात संबद्ध देशों से भारत में सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है।

**ख.** घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित संबद्ध आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

98. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जां शुरू की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था। निर्यातकों, आयातकों, और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए समुचित अवसर प्रदान किए गए थे। पाटनरोधी नियमावली के संबंध में पाटन, क्षति और उसके कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और आयोजित करने तथा इस प्रकार के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई सकारात्मक पाटन मार्जिन और वास्तविक क्षति को सिद्ध करने के बाद, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना पाटन और क्षति से बचने के लिए आवश्यक है।

99. अपेक्षाकृत कम शुल्क नियम के संबंध में, प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से जो भी कम हो, उसके समतुल्य निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई तालिका के कॉलम-8 में दर्शायी गई राशि के समतुल्य पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

**शुल्क तालिका**

क.सं.	उप-शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2924 19	<b>डीमिथाइल एसेटामाइड (डीएमएसी)</b>	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	<b>हेनान जुनहुआ डेवलपमेंट कं. लि.</b>	<b>हेनान जुनहुआ डेवलपमेंट कं. लि.</b>	141	मी.ट.	अम.डॉ.
2	2924 19	<b>डीमिथाइल एसेटामाइड (डीएमएसी)</b>	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	झेजियांग जिआनशांग कैमिकल कं. लि.	झेजियांग जिआनशांग कैमिकल कं. लि.	87	मी.ट.	अम.डॉ.
3	2924 19	<b>डीमिथाइल एसेटामाइड (डीएमएसी)</b>	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	उपरोक्त क्र. सं. 1 तथा 2 में उल्लिखित से इतर अन्य कोई संयोजन		211	मी.ट.	अम.डॉ.
4	2924 19	<b>डीमिथाइल एसेटामाइड (डीएमएसी)</b>	चीन जन. गण.	उन देशों से इतर कोई देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	कोई	कोई	211	मी.ट.	अम.डॉ.
5	2924 19	<b>डीमिथाइल एसेटामाइड (डीएमएसी)</b>	उन देशों से इतर कोई देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	चीन जन. गण.	कोई	कोई	211	मी.ट.	अम.डॉ.
6	2924 19	<b>डीमिथाइल एसेटामाइड (डीएमएसी)</b>	टर्की	टर्की	कोई	कोई	48	मी.ट.	अम.डॉ.

7	2924 19	<b>डीमिथाइल एसेटामाइड (डीएमएसी)</b>	टर्की	उन देशों से इतर कोई देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	कोई	कोई	48	मी.ट.	अम.डॉ.
8	2924 19	<b>डीमिथाइल एसेटामाइड (डीएमएसी)</b>	उन देशों से इतर कोई देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	टर्की	कोई	कोई	48	मी.ट.	अम.डॉ.

\*सीमाशुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह इस जांच के कार्य क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

100. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयात का पहुँच मूल्य सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1962, के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और उसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क के सभी शुल्क शामिल होंगे।

#### आगे की प्रक्रिया

101. केन्द्र सरकार द्वारा इसे स्वीकार कर लिए जाने के बाद इस अंतिम जांच परिणाम के विरुद्ध कोई अपील सीमाशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2018

### FINAL FINDINGS

**Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of 'Dimethylacetamide' originating in or exported from China PR and Turkey.**

**No. 14/41/2016-DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act ) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof, M/s Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd and M/s Balaji Amines Ltd (hereinafter referred to as “the petitioners” or “the applicants”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as “the Authority”) in accordance with the Act and Rules, for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of “Dimethylacetamide” (hereinafter also referred to as the “subject goods” or “product under consideration”), originating in or exported from China PR and Turkey (hereinafter also referred to as the “subject countries”) alleging dumping of subject goods from subject countries and consequent injury to the domestic industry and requested for levy of anti-dumping duties on the subject goods.

2.And whereas the Authority on the basis of prima facie evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No.14/41/2016-DGAD dated 17.03.2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject anti-dumping investigation in accordance with the sub Rule 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**A. PROCEDURE**

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation;

- i. Preliminary scrutiny of the application showed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the Applicants. The application was, therefore, considered as properly documented. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicant to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries. The Authority issued a Notification dated 17th March, 2017, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods.
- ii. The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule 5(5) of the AD Rules.
- iii. Post initiation, the Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification as per Rule 6(2) of the AD Rules.
- iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- v. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules;
  - a. Dupont Trading (Shanghai) Co Ltd, China PR
  - b. Farmasino Pharmaceuticals (Jiangsu), China PR
  - c. Henan Junhua Development Co. Ltd, China PR
  - d. Sinochem Jiangsu Co. Ltd, China PR
  - e. The Chemours Chemical (Shanghai) Co., Ltd, China PR
  - f. Zhejiang Medicines & Health Products Imp & Exp Co Ltd, China PR
  - g. Ak-Kim Kimya As, Turkey
  - h. Dormex Trade & Investments Co. Limited, Turkey
  - i. Enplast Plastik, Turkey
- vi. In response to the initiation notification and intimation, following exporters / producers from China PR have responded by filing Exporter's Questionnaire Response;
  - a. Henan Junhua Development Co., Ltd, China PR
  - b. Zhejiang Jiangshan Chemical Co., Ltd, China PR
- vii. Only Henan Junhua Development Co., Ltd from China PR filed supplementary questionnaire responses to claim MET. The claim of MET however has subsequently been withdrawn.
- viii. No reply to the Exporter's Questionnaire was filed by any producer/exporter from Turkey. The submissions were only made by the Embassy of Turkey in India.
- ix. The Authority forwarded copy of the Initiation Notification to the following known importers/users/user associations of subject goods in India, whose names and addresses were made available to the Authority, and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4):
  - a. Amjey Chem Trade P. Ltd.

- b. Bharat Jyoti Impex
  - c. C J Shah & Co.
  - d. Charmie International
  - e. Chemical Suppliers India (P) Ltd.
  - f. Chemtrade Overseas Pvt. Ltd.
  - g. Deccan Fine Chemicals (India) Private Limited
  - h. Dhanuka Laboratories Ltd.
  - i. Heavy Chemicals Coop
  - j. Hindustan Speciality Chemicals
  - k. Hospira Healthcare India Private Limited
  - l. Indorama Industries Limited
  - m. Jash Pharma Chem
  - n. K. Uttamlal & Company
  - o. Ketul Chem Pvt. Ltd.
- i. None of the importers/users have filed any Importer Questionnaire response except Chemical Suppliers India (P) Ltd, which too is incomplete and not in the prescribed manner. However, the response filed by the said importer is considered in this disclosure statement to the extent found relevant.
  - ii. The Authority made available non-confidential version of the evidences presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7)
  - iii. The Non-injurious Price (NIP) is based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-dumping Rules. It has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
  - iv. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.
  - v. Verification of the information provided by the domestic industry and also the exporters was carried out to the extent deemed necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary.
  - vi. Arguments raised and information provided by various interested parties during the course of the investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been considered by the Authority.
  - vii. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in hearings held on 16.01.2018. All the parties attending the oral hearing were requested to file their written submissions and also rejoinders and such submissions have also been considered.
  - viii. The Authority has considered 1st April, 2015 to 30<sup>th</sup> September 2016 (18 months) as the POI so as to undertake analysis on the most recent data. Thus, investigation was carried out for the period starting from 1st April 2015 to 30<sup>th</sup> September, 2016 (POI). The examination of trends, in the

context of injury analysis, however, covered the periods Apr'12-Mar'13, Apr'13-Mar'14, Apr'14-Mar'15 and the period of investigation.

- ix. Import information as per secondary sources (IBIS) has been provided in the application by the applicant and the same has been relied upon at the initiation stage. However, the Authority has relied upon the transaction wise import data as obtained from DGCI&S for the purpose of volume and value of subject goods into the country for the previous years and POI for the purpose of this investigation.
- x. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded views on the basis of the facts available.
- xi. \*\*\*In this disclosure statement represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xii. Exchange rate adopted by the Authority during the POI for the subject investigation is 1 US\$ = Rs. 66.53

#### **B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

4. The product under consideration is 'Dimethylacetamide' [N, N-Dimethylacetamide]. Dimethylacetamide is the organic compound with the formula  $\text{CH}_3\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{CH}_3)_2$  and bears the chemical nomenclature 'N, N-Dimethylacetamide'. Abbreviations like DMAC is also used to denote the product under consideration in the market parlance. It is a clear, colourless- to- yellow liquid soluble in water and other organic substances with a pale amine like or ammoniacal odour.
5. The subject goods is used as a solvent in the manufacture of Acrylic fibre, solvent in the manufacture of polyester films, as a paint remover, and used as a solvent in Paint stripping because of its very rapid removal action and used both as a solvent as well as reactant in the drug industry. The product is a hazardous chemical and is generally packed in UN approved HDPE drums.
6. Product under consideration is an organic chemical falling under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under custom sub-heading no. 29241900 which is not a dedicated subheading for the PUC. The petitioner submitted that the PUC is primarily declared under Customs subheading 29241900 at the time of imports however, the subheading is indicative only and is not binding on the scope of the PUC since the imports of PUC are reported under numerous other subheadings also. As per the petition, the imports of the PUC have been taking place under other subheadings also such as 29021100, 29051990, 29110090, 29152990, 29153990, 29211110, 29211190, 29212990, 29225090, 29241900, 29242190, 29242990, 29269000 and 20420090. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the proposed investigation and any measures to be recommended to be imposed.
7. Rule 2(d) of the AD Rules defines like article as follows:

*"an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has the characteristics closely resembling those of the articles under investigation".*

8. The applicants have claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the domestic industry. As submitted by the applicants, the subject goods produced by the domestic industry and that imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules.

#### **EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

9. The product under consideration is 'Dimethylacetamide' [N, N-Dimethylacetamide]. Dimethylacetamide is the organic compound with the formula  $\text{CH}_3\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{CH}_3)_2$  and bears the chemical nomenclature 'N,

N-Dimethylacetamide'. Abbreviations like DMAC is also used to denote the product under consideration in the market parlance.

10. 'Dimethylacetamide' is a clear, colourless to yellow liquid soluble in water and other organic substances with a pale amine like or ammoniacal odour.
11. Product under consideration is an organic chemical falling under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under custom sub-heading no. 29241900 which is not a dedicated subheading for the PUC. The PUC is imported under various other subheadings also as seen from the import data. Thus, customs classification is indicative only and not binding on the scope of the PUC and product description alone is dispositive.
12. The Authority has examined the claims of the domestic industry and notes that there is no known difference in subject goods produced by the domestic industry and exported from subject countries. The subject goods produced by the domestic industry and that imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. In view of the above, the Authority holds that the subject goods manufactured by the applicant domestic industry constitutes like article to the subject goods imported into India from the subject countries within the meaning of Rule 2 (d) of the AD Rules.
13. The Authority also notes that there are no contentious submissions made by any of the opposing interested parties vis-à-vis the definition and scope of PUC and the like article aspect in the present investigation. It has been, however, submitted by the Embassy of Turkey that the scope of PUC should be limited to the customs sub-heading and not beyond. It is noted in this regard that limiting the scope of PUC to the customs subheading, which is not even dedicated, shall not be holistic and helpful to identify the imports of PUC for customs purposes. In view of the same, it is found that customs classification shall be indicative only and not binding on the scope of the PUC.

### **C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

14. The present anti-dumping investigation was initiated based on an application jointly filed by Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd and Balaji Amines Ltd.
15. The applicants have claimed that they are the only producers of subject goods in India. As per the evidence available on record, the production of the applicant company constitutes "a major proportion" of the domestic production; in fact 100% share of total domestic production.
16. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under;  
*"(2) (b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are relate to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"*
17. It is noted after examination of relevant facts and rule in this regard that the application based on which the present anti-dumping investigation is initiated has been jointly filed by Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd. and Balaji Amines Ltd as the "domestic industry" concerning the subject goods in India. Rashtriya Chemicals and Fertilizers and Balaji Amines Ltd are found to be the only producers of the subject goods in India. It is also noted that there is no submission disputing this fact by any of the interested parties. It is also claimed by the applicants that they did not import the PUC and are not related to any of the importers or exporters.
18. Since the production of the applicants accounts for "a major proportion" in the total production of the subject goods in India, in fact 100%, the Authority holds that the applicants satisfies the standing criteria under Rule 5(3) and constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules.

**D. CONFIDENTIALITY**

19. There are no substantial submissions made on the confidentiality aspect by the opposing parties. However, it has been contended by the domestic industry, inter alia, that the producer/exporter has held all relevant information confidential in the response filed in the supplementary questionnaire and this has restricted domestic industry from making any factual evaluation about the company and the basis of Market Economy Treatment claims by the producer/exporter from China PR. It has also been submitted that in the absence of such information held as confidential, no corroboration of claims with the facts available can be made by the domestic industry.

**EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

20. The submission with regard to confidentiality made by the applicants and considered relevant by the Authority are examined and addressed herein below.

21. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

*Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule (2), (3) (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

- (2) *The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

- (3) *Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.*

22. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

**E. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN****Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties**

23. There are no substantial submission made by the exporters/importers concerning normal value, export price and dumping margin apart from a claim that China PR should be treated as market economy country and that normal value for Chinese producers should be based on their cost/price as applicable. However, Market Economy Treatment (MET) claim by one of the participating producer/exporter also has been withdrawn.

**Views of the Domestic Industry**

24. Following submissions have been made by the domestic industry concerning normal value, export price, dumping margin and MET claims;
- a. Dumping margin as provided in the petition is above the de-minimis threshold as provided in the Rules and also significant in case of exports from both subject countries namely, China PR and Turkey.

- b. Only two exporters responded in the present investigation from China PR. However, there is no response filed by any producer/exporter from Turkey. In absence of any Exporter's Questionnaire (EQ) Response from any producer/exporter from Turkey, dumping margin/injury margin in case of Turkey needs to be determined based on the best available information in the petition concerning normal value and export price including the details relevant to determine landed price in India for the purpose of injury margin.
- c. In case of China PR, out of two producers/exporters who have filed the EQ Responses one has claimed MET. It is requested that any individual margin to such parties be subjected to strict scrutiny of EQ response concerning their exports to India for verification of the claim.
- d. China PR should be treated as Non Market Economy country for the purpose of present investigation and Normal Value in case of Chinese producers/exporters should be determined as per the provisions of Annexure I Para 7 to the AD Rules.
- e. No MET should be granted to Hennan Junhua Development Co., Ltd based on its Response for the following reasons (a) Certain information available in the public domain from the website of the said producer shows that Hennan Junhua Development Co., Ltd is part of a large group company in China PR and MET questionnaire response is not filed by the Group, (b) The publicly available information shows that Hennan Junhua Development Co., Ltd is ultimately owned by China National Chemical Corporation, which is a state owned enterprise. Hennan Junhua Development Co., Ltd having its ultimate ownership with a state owned enterprise needs to establish various facts since its inception to substantiate its claims of MET ,(c) While the ultimate owner is seen as China National Chemical Corporation, the information shows that Hennan Junhua Development Co., Ltd is a subsidiary of Haohua Junhua and Haohua Junhua Group Co., Ltd which also fall under China National Chemical Corporation. Even Haohua Junhua Group Co., Ltd has not come before the Authority by filing MET Response.
- f. State ownership raises many questions relating to Hennan Junhua Development Co., Ltd. The company needs to establish based on facts how the plant was set up with details of investment, who all invested, what was the source of funds, where did the company get the land from and how the payments for the lands were made, what is the details of the loans by the company, how the working capital requirements of the company has been historically met, sources of raw materials and utilities etc and a corroboration of such details needs to be made with the records of the holding companies also to establish that the cost of the company reflected market principles and is not influenced by state interference.
- g. Based on the facts available, Hennan Junhua Development Co., Ltd does not operate under market economy conditions and therefore the cost of production of the company cannot be treated as based on ME principles. The DI cannot compete with such a producer whose cost are influenced by state interference and in all fairness MET claims of Hennan Junhua Development Co., Ltd should be rejected.

#### **EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

- 25. With regard to the submissions made by the petitioner, it is submitted that the commitments under para 15(a) (i) of the Accession Protocol signed by China with WTO requires that the producers under investigation should clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product. In event of this being substantiated, the importing WTO member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability. Further Article 2.2.1.1 of WTO and AD Rules of India requires that the financial records of producer/exporter reasonably reflect the production costs. Therefore, information and supportive evidence thereof in respect of the following is required to be provided.
  - a. Decisions in regard to price, cost, input including raw material, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signal reflecting supply and demand and without significant State interference and whether cost of major inputs substantially reflect market value.
  - b. Production costs and financial situation does not suffer from any distortion.
  - c. The producer/exporter are subject to bankruptcy and property law which guarantees legal certainty and stability for the operation of the firms.
  - d. Exchange rate conversions are carried out at the market rate.



26. It is noted that only Henan Junhua Development Co., Ltd who is a producer and exporter of subject goods from China PR have claimed MET in the present investigation. However, Henan Junhua Development Co., Ltd has subsequently withdrawn its market economy claim during the course of the investigation. Accordingly, the normal value in respect of China has been constructed.
27. With regard to the contentions made by the domestic industry regarding MET claims by Hennan Junhua Development Co., Ltd, it is noted that it is not essential anymore to address these contentions in detail in view of the withdrawal of the MET claim.

**a. Determination of Normal Value**

**i. China PR**

28. Accordingly, in the absence of any reliable price and cost details for the subject goods in any market economy third country, the Authority has constructed the normal value for China PR considering international price for major raw materials and consumption norms for raw materials and utilities and conversion cost of the most efficient constituent of the domestic industry plus reasonable profit. The calculation of Normal Value for all the exporters from China PR is shown in the Dumping Margin Table below.

**ii. Turkey**

29. It is noted that none of the producers/exporters from Turkey has responded or filed exporter's questionnaire response in the present investigation. In view of the same, normal value for Turkey has been constructed considering optimum cost and consumption norms of the most efficient constituent of the domestic industry plus reasonable profit. The normal value so determined is provided in the Dumping Margin Table herein below;

**b. Determination of Export Price**

**i. China PR**

**(a) Henan Junhua Development Co., Ltd, China PR**

30. The Authority notes from the EQ Response filed by Henan Junhua Development Co., Ltd that the company has exported the subject goods to India during the POI directly. The exporter has reported its export to India in their Appendix-2 and claimed adjustments on account of inland freight, ocean freight, insurance and bank charges, credit cost, non-refundable VAT, port handling charges and same have been allowed. Accordingly, the net export price has been determined for this exporter and the same is provided in the dumping margin table below.

**(b) Zhejiang Jiangshan Chemical Co., Ltd, China PR**

31. The Authority notes from the EQ Response filed by Zhejiang Jiangshan Chemical Co., Ltd that the company has exported the subject goods to India during the POI directly. The exporter has reported its export to India in their Appendix-2 and claimed adjustments on account of inland freight, ocean freight, insurance and bank charges, credit cost, non-refundable VAT, port handling charges and same have been allowed. Accordingly, the net export price has been determined for the exporter and the same is provided in the dumping margin table below.

**(c) All other non-cooperative producer/exporters from China PR**

32. The Authority has determined the net export price for other non-cooperative exporters as per the facts available on record. The net export price determined so is provided in the dumping margin table below.

**ii. Turkey**

33. The Authority notes that no producer/exporter from Turkey has responded to the Authority in the present investigation. In view of the non-cooperation, the Authority has determined net export price for all producers/exporters from Turkey on the basis of DGCI&S import data with due adjustments as claimed by the petitioner and the net export price so determined is provided in the dumping margin table below.

**c. Determination of Dumping Margin**

34. Based on the normal value and net export price determined as above, the dumping margin for producers/exporters from subject countries has been determined by the Authority and the same is as under:

S.No	Country	Producer	Exporter	Normal Value - US\$/MT	Net Export price - US\$/MT	Dumping Margin - US\$/MT	Dumping Margin - %	Dumping Margin Range- %
1	China PR	Henan Junhua Development Co., Ltd	Henan Junhua Development Co., Ltd	***	***	***	***	20-30
2	China PR	Zhejiang Jiangshan Chemical Co., Ltd	Zhejiang Jiangshan Chemical Co., Ltd	***	***	***	***	10-20
3	China PR	Any	Any	***	***	***	***	25-35
4	Turkey	Any	Any	***	***	***	***	25-35

**F. Injury Determination****i. Injury Examination****Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties**

35. Following are the injury related submissions made by the exporters/importers and other interested parties in brief :
- The petitioner has not brought about any substantive evidence to prove the condition necessary for initiation of the Anti-Dumping Investigation. It is advised that the initiation of the current investigation should be terminated
  - The petitioner's application for investigation and imposition of Anti-dumping measures on imports of DMAC is clearly short of legal and factual basis.
  - The facts on the record reveal that the petitioner has exaggerated the increased import of the subject product and deliberately invented injury to the Domestic Industry. As a result, if the Investigating Authority continues the investigation, it shall be determined that there is no increase of the subject product which has caused injury to the Petitioner.
  - Exporters is of the opinion that it is without legal and factual basis for the petitioner to claim serious injury, therefore, the Indian Authority is advised to reject the claim accordingly. The claims of the petitioner are contrary to the published information and appear to be concocted and fabricated to show injury to the Petitioner.
  - The sales by DI remained almost same and the DI performed poorly when the demand was high.
  - There is no co-relation between landed price of imports and sales price of DI as landed price has declined in the POI whereas selling price has increased.
  - The domestic sales of the petitioner have not deteriorated drastically.
  - The market share of the DI increased during the POI.
  - One of the main causes of injury is increased number of employees and wages.
  - The capacity utilization of the DI has increased.
  - Price undercutting has been negative in the entire injury period. This shows no price effect.

- l) Since the DI has increased its capacity, the DI does not face any issue on ability to raise capital investments.
- m) One of the producers namely Balaji Amines limited is doing well and for the said reason cost allocation between PUC and Non PUC should be examined.
- n) 22% ROI for the purpose of NIP is not justified in the present case. There are decisions of the Hon'ble CESTAT in this regard which shows it is improper to apply such percentages for the purpose of NIP.
- o) There was no dumping of products under consideration imported from the subject countries and imported products did not cause injury or injury threat to Indian domestic industry. To apply anti-dumping measures in this case will be inconsistent with the long-term and overall interests of the Indian domestic industry and its downstream industries.
- p) Exporters believe that the purpose of anti-dumping investigation is to protect the fair international trade order. Improper implementation of anti-dumping measures as means of trade protection will cause an unfair competitive environment and cause damage to the fundamental interests of their respective industries in the long term.
- q) As per Turkey's dedicated code concerning the PUC, exports of subject goods to India declined. In such a scenario, imports from Turkey are not a reason for increase in imports of PUC into India. India has always been enjoying a trade surplus against Turkey, which is ranged at 5-6 billion annually.
- r) No cumulative assessment should be done in the present case and a separate examination of impacts of imports from China and Turkey should be done.
- s) During the injury period, the domestic industry has shown positive trends on various parameters. The trend remained positive in terms of market share, sales, production, capacity, productivity, profits, investments etc.
- t) In view of no injury from imports from Turkey, the Indian Authority should act in line with Article 3.2 of the AD Agreement and Indian AD Laws which should lead to the termination of present case.
- u) Exporters have raised an issue of inconsistency in data filed by domestic industry at various point of time such as at the time of initiation (17<sup>th</sup> Jan,2017) post initiation (28<sup>th</sup> April,2017) and written submission (23<sup>rd</sup> Jan,2018)

36. Following are the injury related submissions made by the domestic industry in brief;

- a) The injury data relevant for the present investigation shows the DI has suffered material injury on account of dumping of subject goods from subject countries.
- b) It can be seen from the injury statement that the imports of subject goods from subject countries have increased substantially over the injury period. The volume of imports which was about 2319 MT in the base year increased to a 3501 MT level in the POI. Though the import from Turkey over the base year declined by the POI, the imports in terms of percentage in total imports to India stood at about 18% which is much higher than the statutory threshold of 3% and was at dumped prices.
- c) While the imports from subject countries increased significantly in absolute terms and also in relation to production and consumption, the import price which was about Rs76.14 per kg (CIF) in 2012-13 declined to Rs71.17 per Kg (CIF) in the POI. In fact, import price from both the countries have declined and the incidence of dumping margin in such import from Turkey is in the range of 15-30% and from China PR it is in the range of 20-35%.
- d) The capacity with the company has been 7500 MT during the entire injury period and production, capacity utilization and sales has shown marginal increases over the injury period but remained at below par levels owing to the presence of dumped material. The capacity

utilization was only about 53.66% in the POI which was about 45% in the base year. Such a low level of capacity utilization cannot be seen as any reasonable level of capacity utilization and such low capacity utilization is the result of high penetration of dumped imports of subject goods in the Indian market. Thus, material injury in terms of subdued levels of production, capacity utilization and sales are very apparent.

- e) The market share of the DI which was 44% in the base year could only increase to 48% whereas the market share of the dumped imports increased from 31% in the base year to 44% in the POI which shows that the dumped imports is capturing the market share in a consistent and substantial manner. Injury on account of market share is thus visible. In the absence of dumped imports, DI would have produced and sold much more in line with the demand for the product under consideration in India.
- f) The cost of sales of the DI increased from a 100 basis point to 129 points in the POI whereas selling price could only increase to 103 points which shows that increase in selling price was much lower than the increase in cost of production. This shows the DI was not in a position to pass on even its full cost to the customers due to the presence of dumped imports. The DI was in fact making cash losses during the injury period. Thus, price suppression and depression are apparent.
- g) The landed prices of imports from subject countries were creating price undercutting effects which in fact prevented the DI from raising its prices. The DI was put in an adverse situation to decide its price based on the landed price of dumped imports and not based on a fair price method so as to recover the cost and also gain a reasonable profit. Thus, serious price effect on the performance and pricing abilities of the DI is very visible which indicates that the DI has suffered material injury.
- h) Apart from cash losses; PBIT, ROCE, growth on price parameters etc. also remained negative which is directly on account of the dumping of the subject goods from subject countries and the situation continues unabated.
- i) The level of employment marginally increased in line with the marginal increase in production. It is submitted in this regard that the DI has the potential to employ more if a fair situation is established in the market and the DI is able to run its plant at moderate levels.
- j) Also, productivity and wages per unit showed improvement and increase respectively. However, the increases in wages over the years cannot be noted as abnormal (100 to 128 points) and are as per the wage laws of the land. Thus, it cannot be said that the claimed injury are on account of any abnormal wages paid by the company.
- k) The position of ROCE remains a huge worry for the DI as the same is significantly negative which means that the investments made by the company is not paying off and it is in fact impacting the long term prospects of the company apart from the material injury that is being suffered.
- l) The growth of the company has been negative on all major parameters. This shows that the DI has suffered material injury in terms of growth as well.
- m) The information in the petition shows that although some injury indicators such as production volumes, capacity utilization, sales and market share followed some marginal increases but overall subdued position, all the parameters showing financial situation of the domestic industry, namely profitability, return on investment, cash profit etc. has been significantly negative during the POI. Thus, the domestic industry has faced financial losses on account of aggressive dumping adopted by producers/exporters from subject countries and the situation points to material injury.
- n) An objective and holistic evaluation of various economic parameters as above clearly demonstrate that dumped imports from subject countries have caused material injury to the domestic industry and the same is visible both on volume and price parameters. The price effect of the dumped imports has been even significant which is seen in terms of losses, price suppression and price depressions as a result of which profitability of the domestic industry

eroded and the domestic industry became loss making with negative returns and negative growths in various parameters.

- o) Thus, the analysis of injury clearly shows that the DI has suffered material injury and dumped imports have triggered such an injury.
- p) The exporters have contended that i) the petitioner has not brought any substantive evidence to show dumping and injury and the case should be terminated for this reason, ii) the petition is clearly short of legal and factual basis, iii) the petitioner has deliberately exaggerated the import volume and deliberately invented injury and iv) claims of injury has no basis. Petitioner denies all such contentions as self-serving and bereft of any merit. It is submitted that the petition contained prima facie evidence of dumping and consequent injury to the DI and such information has been submitted in the prescribed formats and also by elaborating of the facts by providing the sources of various information relied upon. Thus, the Authority had adequate information to justify the initiation of the present investigation to conduct a detailed investigation. Thus, the initiation and present investigation meets all legal and factual requirements. Import data concerning the subject goods is available as per DGCI&S and the same is relied upon by the DI and the transaction wise details of the same is provided to the opposing parties also. Not even a single transaction is pointed out as incorrectly included by the DI. Anyways, it is apparent that the import being very high in 2014-15 coincided with a high demand and the same declined in the POI but have still shown increase over the base year. Thus, there isn't anything which suggests the import data as per DGCI&S is not correct.
- q) The exporters have claimed that the petition does not contain adequate evidence of dumping and/or injury to justify initiation and said that imports from subject countries have decreased. The contentions are denied as factually wrong. The base year of the injury period in the present case is 2012-13 and a comparison has to be made between the said base year and POI. The exporter has conveniently picked 2014-15, which is the immediate previous year, as the base year to say that imports have decreased. It can be seen that imports from subject countries increased over the base year in absolute terms. There were some spike in imports during 2014-15 as per the data and thereafter imports reduced in the POI. This doesn't show that the imports were negligible or imports decreased as interpreted by the exporter. Imports from subject countries were above the de-minimis thresholds at dumped prices as stipulated in the law and also have increased from a 2319 MT in the base year to 3501 MT in the POI which shows clear increases, thus, the claims of the exporter needs to be rejected. Since cumulative assessment is relevant in the present case, decline in imports from Turkey is insignificant. Nevertheless, imports from Turkey, which was much above the legal threshold of 3% of the total imports, was at dumped prices. Thus, imports from Turkey has also caused injury to the DI and have been included in the scope of present investigation very correctly.
- r) The exporters have claimed that the sale by DI remained almost same and the DI performed poorly when the demand was high. It may be noted in this regard that the sales by the DI remained sluggish because of the presence of dumped imports from subject countries. When the demand was highest in 2014-15, the share of dumped imports in demand was also highest at 69.50% which was 31% in the base year. As a result of the same, the share of DI dipped to 26.58% in 2014-15 from a 44% in the base year. Thus, the DI did not get the benefit of such increases in demand because of the presence of dumped imports.
- s) The exporters have contended that there is no co-relation between landed price of imports and sales price of DI and for this they have cited that the landed price have declined in the POI whereas selling price increased. It is to be noted here that the analogy by the exporter is not correct. Though the landed price declined, the landed price during the POI were creating positive price undercutting effects which shows the DI was forced to keep its price in line with the landed price of such dumped imports which has created adverse price effects on the performance of the DI which is seen on the losses suffered by the DI.
- t) It has been contended by the exporters that the domestic sales of the petitioner has not deteriorated drastically whereas export performance of the petitioner deteriorated drastically. It is submitted that the contention is not contextual to the claims of injury. The injuries

claimed are concerning domestic operation only. Exports by the petitioner were very nominal and exports were not in losses. Thus, the contention of the exporters that injury is on account of decline in exports is not of any basis.

- u) The exporters have contended that the market share of the DI increased by the POI. It is to be noted in this regard that the market share of dumped imports has been about 48% which was higher than the DI. With such huge share of dumped imports in the Indian market, the DI could not achieve a fair price and share for its product and as a result suffered material injury. Thus, an increase in market share did not ensure overall positive performance of the DI.
- v) The exporters have contended that one of the main causes of injury is increased number of employees and wages. The contention is bereft of any truth. The level of employment marginally increased in line with the marginal increase in production. It is submitted in this regard that the DI has the potential to employ more if a fair situation is established in the market and the DI is able to run its plant at moderate levels. Also, productivity and wages per unit also showed improvement. However, the increases in wages over the years cannot be noted as abnormal and are as per the wage laws of the land. Thus, it cannot be said that the claimed injury are on account of any abnormal wages paid by the company or increases in employment. Also, it is baseless a claim that the number of employees increased when the capacity remained the same. Employment is connected with the production and the company could have employed much more at this level of capacity utilization.
- w) It is contended by the exporters that the capacity utilization of the DI has increased. The claims are misleading. Even after minor increases in production, the capacity utilization remained at 56% during the POI which is a sub-optimal level and not a reasonable level given the demand for the product in India. The DI cannot sustain with such low level of Capacity Utilization.
- x) The exporters have assumed that price undercutting has been negative in the entire injury period. It is submitted in this regard that the presumption of the exporter is not correct. Price undercutting has been positive in the POI from subject countries.
- y) It is contended by the exporters that since the DI increased its capacity the DI does not face any issue on ability to raise capital investments. The contention is not factually correct. The DI did not increase the capacity and the capacity remained the same throughout. The DI cannot plan any future investments in a situation where dumping and injury is continuing unabated.
- z) It is contended by the exporters that one of the producers namely Balaji Amines Limited is doing well and for the said reason cost allocation between PUC and Non PUC should be examined. It is submitted that the apprehension of the exporter is out of place and the petitioners do not have any objection to any amount of scrutiny of data by the Authority. The basis of allocation of cost between PUC and Non PUC is done based on accepted principles and the insinuations of the exporter are not bonafide. Also, the AD scheme itself is product specific and what is relevant is the performance of the DI qua the like article and not the overall performance of the petitioner company.
- aa) The exporters have contended that 22% ROI for the purpose of NIP is not justified. We deny all the claims of the exporter as bereft of any merit. The DA has consistently been applying such practices in many cases and the facts of the present case also warrant such approach and at least 22% is essential. There are no judgments by any forum which says DA cannot apply 22% ROI for the purpose of NIP. On the contrary, the jurisprudence as interpreted by Hon'ble CESTAT remains that the practice of the DA applying 22% is consistent and nothing inappropriate in it is found.
- bb) With regard to Embassy of Turkey's claim that imports of subject goods have declined and there is no injury because of such import, it is submitted that reduction in import does not negate injury. Even after such decrease, the volume of imports from Turkey was about 18% in the total imports whereas the threshold as per the AD Agreement itself is only 3%. The

imports from Turkey were at dumped prices as well. Thus, imports from Turkey also contributed to injury to the domestic industry and the factual ingredients necessitate a cumulative assessment of injury in the present case.

### **EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

37. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
38. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry Rule 11 of AD Rules read with para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows.

*“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”*

39. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the opposing interested parties and also domestic industry. However, certain specific submissions made by the interested parties have been addressed by the Authority as under :
- a) With regard to the contention that the petitioner has not brought about any substantive evidence to prove the condition for initiation of the Anti-Dumping Investigation, it is noted that the present investigations were initiated based on receipt of prima facie evidences to justify an initiation.
  - b) With regard to the contention that the petitioner's application for an investigation and imposition of Anti-dumping measures on imports of DMAC is short of legal and factual basis, it is noted that the case was initiated upon prima facie evaluation of the evidences furnished in the application.
  - c) With regard to the contention that the claims of the Petitioner are contrary to the Published information and appear to be concocted and fabricated to show injury to the Petitioner, it is noted that the Authority considered only verified information concerning injury so far it is relevant for the subject goods.
  - d) With regard to the submission that as per Turkey's dedicated code concerning the PUC, exports of subject goods to India has declined and in such a scenario, imports from Turkey are not a reason for increase in imports of PUC into India, it is noted that imports from Turkey remained at about 18% in total imports into India with positive dumping margin and in such a scenario investigation against Turkey was unavoidable as per the Law.
  - e) With regard to the contention that India has always been enjoying a trade surplus against Turkey, which is ranged at 5-6 billion annually, it is noted that the present investigation has a limited scope of examining dumping of PUC and injury caused to the domestic industry producing the like article in India.
  - f) With regard to the contention that no cumulative assessment should be done in the present case and a separate examination of impacts of imports from China and Turkey should be done, it is noted that cumulative assessment is justified in the present case for the reason elaborated at appropriate places in this disclosure statement.

- g) With regard to the contention that during the injury period the domestic industry has shown positive trends on various parameters and that the trend remained positive in terms of market share, sales, production, capacity, productivity, profits, investments etc, the examination of injury conducted in this disclosure statement ipso facto addresses the submissions.
- h) With regard to the contention that in view of no injury from imports from Turkey, the Indian Authority should act in line with Article 3.2 of the AD Agreement and Indian AD Laws which should lead to the termination of present case, it is noted that this issue has been dealt with appropriately in this disclosure statement at relevant places.
- i) With regard to the issue of inconsistency in the data filed by the Domestic industry at different stages, DI has contended that data filed during the initiation was for 15 months and the post initiation data was for POI which was for 18 months and on account of such change in period there was a change in the indexed data.
- j) Further, DI has contended that while filing the petition RCF treated sales to EOU as exports and accordingly the volume and value of such sales was treated as exports but subsequently all such sales to EOU were treated as domestic sales because it was treated so in the Cost Audit Report and therefore the effect of such change has been on the volume of sales and all price related parameters. It is noted that the explanation furnished by the DI appears plausible.
- k) As regards Balaji Amines the petitioner on their written submission agreed that there was a mistake on the part of the company on reporting capacity. The actual capacity throughout the injury period was 2,500 MT and evidence of the same was submitted to the Authority during the on the spot verification at the site of the company. As regards cost and price for the POI, the same was submitted provisionally at the time of initiation and currently the data is as per the verified data by the Authority.

#### **Cumulative Assessment**

40. Article 3.3 of WTO agreement and Annexure II para (iii) of the Anti-dumping Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- a. *The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and*
  - b. *Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.*
41. The Authority notes in this respect that:
- a) The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the de minimis limits prescribed under the Rules.
  - b) The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
  - c) Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.
  - d) Decrease in imports from Turkey cannot be seen as factor to conduct separate analysis for Turkey. Even after such declines, imports from Turkey stood at significant levels and the imports from Turkey were also at dumped prices.



42. In view of the above, the Authority considers that it would be appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from exports of the subject goods from the subject countries.

**ii. VOLUME EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS ON THE DOMESTIC INDUSTRY**

**a. Demand and market share**

43. Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of like article by all the Indian Producers and imports from all sources. The Authority has considered imports into India as per DGCI&S transaction-wise import data to determine the volume and value of imports of PUC into India from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

**i) Demand**

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI(Annualised)
Demand	MT	7,458	8,041	9,915	7,912
Indexed	Trend	100	108	133	106
Imports from Subject Countries	MT	2,319	2,930	6,891	3,501
Imports from Other Countries	MT	1,854	1,930	389	648
Sales of Domestic Industry	MT	3,284	3,180	2,635	3,763

**ii) Market Share of domestic industry and imports in Demand**

44. Considering imports of subject goods from various sources and sales of subject goods of the Indian Producers, demand was determined and further market share of subject imports, domestic industry and other imports in such demand in India was also examined and the factual position in this respect is as follows;

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI (Annualised)
Sales of Domestic Industry	%	44.04	39.56	26.58	47.55
Imports from Subject Countries	%	31.10	36.44	69.50	44.25
Imports from Other Country	%	24.86	24.00	3.92	8.19

45. It is seen from the above tables that demand for the product in the country in the POI has shown increase as compared to the base year but decline as compared to demand in the preceding two years. The market share of the domestic industry which was 44.04% in the base year declined to 26.58% in 2014-15 but increased again to 47.55 in the POI. The share of imports from subject countries witnessed increase from 31.10% in the base year to 44.25% in the POI. However, it was less compared to share of 69.50% in the preceding year.

**b. Import volume and market share of subject countries**

46. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject goods from the subject country has been analysed as under in this respect.

47. The Authority has examined the volume of imports of the subject goods as per the transaction wise import data provided by DGCI&S. On the basis of this import data on record, the import volume from each subject countries is found to be above the de-minimis levels. Imports volume from subject countries and other countries has been as under: -

Particulars		Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI (Annualised)
Volume	China PR	MT	654	1549	6344	2731
	Turkey	MT	1,666	1,381	547	770
	Subject Countries Total	MT	2,319	2,930	6,891	3,501
	Other countries	MT	1,854	1,930	389	648
	Total imports	MT	4,173	4,860	7,280	4,149
Market Share in Imports	China PR	%	15.66	31.88	87.14	65.83
	Turkey	%	39.91	28.41	7.52	18.55
	Subject Countries	%	55.58	60.29	94.66	84.38
	Other countries	%	44.42	39.71	5.34	15.62

48. The imports from subject countries which were 2,319 MT in the base year increased to 3,501 MT during the POI. However, it has witnessed significant decline from the import volume of 6891 MT in the immediate preceding year. Thus, there is no clear trend visible.
49. As regards unusual increase in imports during 2014-15, the petitioner has claimed that the PUC is used as a solvent as well as reactant in drug industry. The major consumption of DMAC is in a drugs called Cefuroxime Axetil produced by Aurobindo Pharma, Covalent Laboratories, Davis Laboratories, Orchid Chemicals etc. During the year 2014-15 there was an unusual demand for this antibiotic both in India and abroad and hence the demand for DMAC had grown significantly in that particular year and consequently imports of the PUC by these companies during the year 2014-15. The above argument of the petitioner was verified from the transaction wise DGCI&S data and it was found these pharmaceutical companies had imported \*\*\* MT of PUC in the year 2014-15 as compared to \*\*\* MT of imports in 2015-16.

**c. Share of dumped imports in relation to production and consumption**

50. The relevant information concerning share of dumped imports in relation to production and consumption is seen as follows;

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI (Annualised)
Imports from Subject Countries	MT	2,319	2,930	6,891	3,501
Production of domestic industry	MT	3,410	3,149	2,879	4,025
Imports from subject countries in relation to production of domestic industry.	%	68.01	93.05	239.35	87.00
Imports from subject countries in relation to consumption in India	%	31.10	36.44	69.50	44.25

51. It is noted that imports from subject countries increased in absolute terms and also in relation to production and consumption in India till 2014-15 and then registered decline.

**i. PRICE EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS ON THE DOMESTIC INDUSTRY**

52. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

*"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."*

53. It has been examined whether there has been price undercutting by the dumped imports of the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the weighted average cost of production (COP), weighted average Net Sales Realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject countries at the appropriate sections below.

**a) Price Undercutting**

54. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level. The domestic prices and margin of undercutting is shown as per the table below:

Particulars	Unit	China PR	Turkey	Subject Countries
Landed Value	Rs./KG	75.57	77.89	76.08
Net Sales realization	Rs./KG	***	***	***
Price Undercutting	Rs./KG	***	***	***
Price Undercutting	%	0-5	Negative	0-5

55. The authority notes that the price undercutting has been just marginally positive from subject countries in the POI.

**b) Price suppression/depression**

56. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority examined the changes in the costs and prices over the injury period. The factual position is shown in the table below:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI(Annualised)
Cost of production	Rs./KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	136	129
Selling Price	Rs./KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	114	103
Landed Value (Subject Countries)	Rs./KG	81.39	85.73	83.66	76.08
Trend	Indexed	100	105	103	93

57. It can be seen from the above table that the cost of production increased from 100 indexed points in the base year to 129 points in the POI, whereas the selling price moved from 100 indexed points in the base year to 103 indexed points in the POI. In the same period landed price of imports from subject countries declined from a 100 indexed points in the base year to 93 points in the POI which shows the domestic industry had reduced the selling price to match the landed value of imports from subject countries. Price suppression is evident due to the fact that the domestic industry could not increase its prices in proportion to increase in costs. Price depression is also evident during POI.

#### **G. Economic parameters of the domestic industry**

58. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

##### **a. Capacity, Production & Capacity Utilization**

59. Capacity, production and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the following table:-

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI ( Annualised)
Capacity MT	MT	7,500	7,500	7,500	7,500
Production	MT	3,410	3,149	2,879	4,025
Capacity utilization	%	45.47	41.99	38.39	53.66

60. It is observed that capacity with the domestic industry remained the same throughout the injury period and production of the domestic industry and capacity utilisation increased during the injury period and also POI. It is however, noted that capacity utilisation even after increases has been at 53.66% which is claimed to be a sub-optimal level by the domestic industry.
61. It has been contended by the opposing parties that the domestic industry has admittedly changed the total capacity information subsequently at the time of written submission. The Authority has subjected the claims of the petitioner in this regard to scrutiny and verification and finds that the capacity set up by the domestic industry is 7500 MT per annum.

##### **b. Sales volume and market share**

62. Sales volume and market share of the domestic industry is as given in the following table:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI ( Annualised)
Domestic sales	MT	3,284	3,180	2,635	3,763
Demand	MT	7,458	8,041	9,915	7,912
Market Share of domestic industry in Demand	%	44.04	39.56	26.58	47.55

63. It is noted that sales of the domestic industry showed increases during the POI over the base year. It is, however, noted that the increases in market share of imports from subject countries has been higher than that of the domestic industry.

**c. Inventories**

64. The position of inventories noted as average stock with the domestic industry moved as follows;

	Units	2012-13	2013-14	2014-15	POI (Annualised)
Average Stock	MT	39	27	114	367

65. The Authority notes that the inventory level of the Domestic Industry has seen increase in the POI but it is equivalent to approximately one months' requirement.

**d. Profit/Loss**

66. The profitability of the domestic industry is given in the following table:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI (Annualised)
Profits	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(167)	(2767)	(3284)
Profits	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(161)	(2220)	(3762)

67. It is noted that the domestic industry has been suffering financial losses concerning the subject goods and the losses were highest during the POI.

**e. Return on capital employed**

68. Information regarding return on capital employed is given in the table below;

	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI (Annualised)
Profit Before Interest and Tax	Rs Lacs	***	***	***	***
Capital Employed	Rs Lacs	***	***	***	***
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(53)	(4563)	(7775)

69. The Authority notes that return on capital employed of the domestic industry has been negative throughout the injury period including during the POI. Though the ROI was marginally negative in the base year, it has become significantly negative in the POI.

**f. Cash Flow**

70. Authority has examined the trends in cash profits in order to examine the impact of dumping on cash flow situation of the domestic industry. Information regarding cash profit of the domestic industry is given in the following table;

	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI (Annualised)
Cash Profits	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	139	(603)	(1,251)

71. It is seen that the cash profits of the domestic industry declined over the injury period and has been negative in the POI in comparison to the base year.

**g. Factors affecting domestic prices**

72. The examination of the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc. shows that the selling prices have not witnessed increase in proportion to the increase in cost on account of declining import prices, thereby causing price suppression.

**h. Productivity**

73. Information regarding productivity is given in the table below;

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI (Annualised)
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	77	94
Productivity per day	MT/day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	92	84	118

74. It is noted that productivity of the domestic industry per employee marginally declined over the base year however the same increased over the immediate previous year.

**i. Employment and Wages**

75. Information regarding employment and wages is given in the table below;

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI (Annualised)
Employment	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	110	125
Wages	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	137	128

76. It is noted that the employment level of the domestic industry has increased over the injury period and during the POI. Wages per kg has have also shown increases during the POI over the base year and decline over the immediate previous year.

**j. Growth**

77. It is noted that growth of the domestic industry has been negative in a number of core parameters. Such negative growth is visible when the demand for the product has shown consistent growth.

**k. Ability to raise capital investment**

78. The Authority notes that the domestic industry currently has the capacity to meet the Indian demand and question of ability to raise capital investment would be relevant for potential investments.

**I. Level of dumping & dumping margin**

79. It is noted that the imports from the subject countries are entering the Indian market at dumped prices and the margins of dumping are significant.

**H. CONCLUSIONS ON INJURY**

80. The dumping margin determined by the Authority is significant. Dumped imports have had adverse price effect in terms of price suppression. Effect of dumped imports has prevented the domestic industry from raising prices of the subject goods in line with increase in costs leading to financial losses.

81. With regard to consequent impact of the dumped imports on the domestic industry, it is noted that volume parameters such as production, sales and capacity utilisation have increased by the POI though the capacity utilisation remained at about 54% and inventories increased. In terms of price parameters, the domestic industry has suffered cash losses and associated profit parameters including ROCE has been negative. This needs to be seen in the light of price suppression created by dumped imports. Thus, dumped imports from the subject countries have adversely impacted the performance of the domestic industry in respect of profits, cash profits and return on investment etc.

**I. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN**

82. The Authority has determined Non Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in anti-dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP of the domestic industry has been determined plant wise and accordingly weighted average NIP has been worked out. The non-injurious price so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject countries to determine the injury margin as follows;

S.No	Country	Producer	Exporter	Non Injurious Price – US\$/MT	Landed price - US\$/MT	Injury Margin - US\$/MT	Injury Margin - %	Injury Margin Range - %
1	China PR	Henan Junhua Development Co., Ltd	Henan Junhua Development Co., Ltd	***	***	***	***	10-20
2	China PR	Zhejiang Jiangshan Chemical Co., Ltd	Zhejiang Jiangshan Chemical Co., Ltd	***	***	***	***	0-10
3	China PR	Any	Any	***	***	***	***	15-25
4	Turkey	Any	Any	***	***	***	***	0-10

**J. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS**

83. Following are the causal link related submissions made by the foreign producers/exporters/ users/ importers etc.;

- There was no dumping of products under consideration imported from the subject countries and imported products did not cause injury or injury threat to Indian domestic industry.
- Injury, if any, is on account of increases in employment and wages.
- Article 3.5 of AD Agreement indicates that any other cause of injury should not be attributed to imports. In the present case, there is a clear drop in the exports made by the petitioners. Also, increasing capacity also needs to be examined in the context of causal link.

84. Following are the causal link related submissions made by the domestic industry;

- Dumping is significant in the present case, domestic industry has suffered material injury and such injury is caused because of the dumping of subject goods from subject countries.

- ii. While the non-attribution analysis provided in the petition establishes that injury to the Domestic Industry has not been caused by any such other factors, petitioners submits that the following parameters establish that the injury to the Domestic Industry has been caused by dumped imports.
- a) The price at which the product under consideration has been imported into India are below its normal value resulting in significant dumping margin;
  - b) The landed prices from subject countries have declined during POI as compared to the previous year as well as base year creating price suppression effect on the domestic industry.
  - c) Presence of imports at dumped price is preventing domestic industry to increase their price to the extent of increase in input cost, thus, imports are suppressing the selling prices of the domestic industry.
  - d) Reduction in profits directly resulted in deterioration in return on capital employed and cash profits and both become negative. The domestic industry has not been able to cover the cost of capital.
85. The Authority has examined whether other factors listed under the Anti-dumping Rules could have contributed to injury to the domestic industry. The examination of causal link between dumping from subject countries and material injury to the domestic industry has been done as follows:
- (a) Volume and prices of imports from third countries**
86. The imports from the countries other than the subject countries are not significant in volume terms so as to cause or threaten to cause injury to the domestic industry. Imports from other countries were at high prices. Thus, it cannot be said that imports from other countries have been causing injury.
- (b) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**
87. It is noted that there is a single market for the subject goods where dumped imports from the subject countries compete directly with the subject goods supplied by the domestic industry. It is also noted that the imported subject goods and domestically produced goods are like article and are used for similar applications/end uses. There is no evidence of trade restrictive practices and competition between the foreign producers and domestic producers causing injury to the domestic industry.
- (c) Contraction of demand or Changes in the pattern of consumption**
88. The Authority notes that demand for the product showed increase during the injury period and also during the POI. Thus, it can be concluded that the injury to the domestic industry was not due to contraction in demand.
- (d) Development in Technology**
89. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the domestic industry.
- (e) Export performance of Domestic Industry;**
90. Claimed injury to the domestic industry is not on account of possible significant deterioration in export performance of the domestic industry. Therefore, any possible decline in export performance is not a cause of any injury.
- (f) Productivity of the Domestic Industry**
91. The Authority notes that the deterioration in productivity has not caused injury to the domestic industry.
- (g) Performance of the domestic industry with respect to other products**
92. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the domestic industry's performance since the information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.



**K. FACTORS ESTABLISHING CAUSAL LINK**

93. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has materially injured over the injury period and during the POI. The causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:

- a) Imports of the subject goods were at dumped prices;
- b) Market share of dumped imports in demand has been about 44% during the POI which is reasonably significant percentage and the same has prevented the domestic industry from producing and selling more which it could have done in the absence of such dumped imports;
- c) The domestic industry had significant unutilised capacity in the POI even though the demand had increased.
- d) There have been suppressive effects on the domestic prices caused by the dumped imports from subject countries.
- e) The domestic industry's profitability and return on capital employed have been adversely affected.
- f) From the foregoing facts and analysis, the Authority notes that the domestic industry has suffered material injury caused by the dumped imports from the subject countries.

94. The above essential facts of the investigation gathered by the Designated Authority during the course of the investigations and analyzed by the Authority in the present disclosure statement were disclosed to the interested parties in order to enable these interested parties to offer their comments on these facts.

**L. POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS BY THE INTERESTED PARTIES**

95. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. Majority of the issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. Additional submissions have been analysed as under:

**Submissions made by the Domestic Industry**

- i. The imports increased throughout the injury period and were higher than the base year during the POI and the decline in the POI was only vis-à-vis the immediate previous year during which some unusual spike in import took place due to some specific demand in pharma sector as understood. Thus, the import has witnessed an overall increasing trend, as apparent from a comparison between base year and the POI.
- ii. There is a mismatch between claimed Net fixed assets of one of the constituent of domestic industry and that allowed by the Authority.
- iii. While calculating working capital, the Authority has not allowed subsidy receivable from the Government and the inventory of bought-out products as current assets. Since the same is not allowed as current assets, it is requested that the Authority may consider total sales of the company net of subsidy and net of bought- out products.
- iv. The authority has considered cost of DMA with reasonable return as transfer price of intermediate. We request the Authority to take selling price as the transfer price for DMA. In case the company did not produce DMA, they were bound to purchase the same. Hence, the selling price must be taken as transfer price.
- v. In the POI the capacity utilization of the company was 92.52% which was best for the POI and previous three years. In spite of that, fixed expenses have been normatted. It seems Authority has changed the allocation of expenses without giving any reasoning for the same.

**EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

i) Return on Fixed assets has been re-examined and it has been observed that during the POI, DMAC plant of RCF Ltd was closed for 253 days. Similarly, during the POI, the DMAC plant of M/s Balaji Amines Ltd was also not in continuous operation and remained closed for some of the days in almost every month to avoid piling up of inventory. The cost of production of RCF has been considered based on the audited cost accounts records assuming that the idle time expenses have been suitably considered by the auditor. Returned on Fixed assets have accordingly been re-examined as per the records maintained by the company.

ii) For M/s RCF Ltd, subsidy receivable from the Government and the inventory of bought-out products have not been allowed as current assets. Since the same has not been allowed as current assets, the total sales of the company has also been considered net of subsidy and net of bought- out products.

iii) M/s Balaji Amines Ltd is manufacturing DMA and using the same for captive consumption for the production of the PUC ( i.e. DMAC). The cost of DMA has been considered as the transfer price and reasonable returns has been provided as per the consistent past practice followed by the Authority.

iv) In the POI, the capacity utilization of M/s Balaji Amines Ltd was 92.52%, which was the best for the POI and previous three years. Therefore, the same has been considered to work out per unit fixed cost as per Annexure III of the Anti-Dumping Rules.

Accordingly, based on above, the revised injury margin is as under:

S.No	Country	Producer	Exporter	Non Injurious Price – US\$/MT	Landed price - US\$/MT	Injury Margin - US\$/MT	Injury Margin - %	Injury Margin Range - %
1	China PR	Henan Junhua Development Co., Ltd	Henan Junhua Development Co., Ltd	***	***	***	***	10-20
2	China PR	Zhejiang Jiangshan Chemical Co., Ltd	Zhejiang Jiangshan Chemical Co., Ltd	***	***	***	***	0-10
3	China PR	Any	Any	***	***	***	***	15-25
4	Turkey	Any	Any	***	***	***	***	0-10

#### **M. Indian industry's interest & other issues:**

96. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

#### **N. Recommendation**

97. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- The product under consideration has been exported to India from the subject countries below normal values.
- The domestic industry has suffered material injury on account of dumped subject imports from subject countries.

98. The Authority notes that the investigation was initiated and it was notified to all the interested parties. Adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the Anti-Dumping Rules and having established positive dumping margin as well as material injury to the domestic industry caused by

such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is necessary to offset dumping and injury.

99. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the anti-dumping duty equal to the amount indicated in Column 8 of the table below is recommended to be imposed for a period of five (5) years by the Central Government on the imports of the subject goods originating in or exported from subject countries.

### **DUTY TABLE**

Sl. No.	Sub-heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
1	2924 19	Dimethyl acetamide (DMAC)	China PR	China PR	Henan Junhua Development Co., Ltd	Henan Junhua Development Co., Ltd	141	MT	US\$
2	2924 19	Dimethyl acetamide (DMAC)	China PR	China PR	Zhejiang Jiangshan Chemical Co., Ltd	Zhejiang Jiangshan Chemical Co., Ltd	87	MT	US\$
3	2924 19	Dimethyl acetamide (DMAC)	China PR	China PR	Any combination other than mentioned in Sl. No.1 & 2 above		211	MT	US\$
4	2924 19	Dimethyl acetamide (DMAC)	China PR	Any country other than those subject to Anti-dumping Duty	Any	Any	211	MT	US\$
5	2924 19	Dimethyl acetamide (DMAC)	Any country other than those subject to Anti-dumping Duty	China PR	Any	Any	211	MT	US\$
6	2924 19	Dimethyl acetamide (DMAC)	Turkey	Turkey	Any	Any	48	MT	US\$
7	2924 19	Dimethyl acetamide (DMAC)	Turkey	Any country other than those subject to Anti-dumping Duty	Any	Any	48	MT	US\$
8	2924 19	Dimethyl acetamide (DMAC)	Any country other than those subject to Anti-dumping Duty	Turkey	Any	Any	48	MT	US\$

\*The customs classification is indicative only and not binding on the scope of this investigation.

100. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

**Further Procedure**

101. An appeal against the order of the Central Government arising out of this Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

SUNIL KUMAR, Addl.Secy. & Designated Authority